

**THE UNTOUCHABILITY (OFFENCES)
AMENDMENT AND MISCELLANEOUS
PROVISION BILL, 1976**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA) : Sir, I beg to move :

"That the Bill to amend the Untouchability (Offences) Act, 1955 and further to amend the Representation of the People Act, 1951, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, the Untouchability (Offences) Act, 1955 was passed in pursuance of Article 17 of the Constitution which has abolished 'untouchability' and has made its practice in any form punishable by law. The Act has been in force for more than 20 years. A Committee was appointed under the Chairmanship of Shri Elayaperumal to go into the working of the Act and on the basis of the recommendations of that Committee, a Bill was introduced in the Lok Sabha in April, 1972.

The Bill was referred to a Joint Committee of the two Houses. The Joint Committee went thoroughly into the various aspects and made many far-reaching changes. The Bill as reported by the Joint Committee has been passed by the Lok Sabha with a few amendments.

The name of the principal Act is being changed to 'the Protection of Civil Rights Act.' So, in future, the name of the Act will be the Protection of Civil Rights Act instead of the Untouchability (Offences) Act.

The present amending Bill considerably tightens the provisions relating to the removal of untouchability. Privately owned places of worship along with lands and subsidiary shrines appurtenant to such privately owned places of worship which are allowed by the owner to be used as places of public worship are being brought within the purview of the Act. The direct or in-

direct preaching of untouchability or its justification on historical, philosophical or religious ground is being made an offence. The compelling of any person to do any scavenging, sweeping removing of carcasses, flaying of animals or removing the umbilical cord is also being made punishable. The State Governments are being empowered to impose collective fines on the inhabitants of any area who are concerned in or abetting the commission of untouchability offences. All untouchability offences are cognizable. They will now become non-compoundable and in cases where the punishment does not exceed three months, they can be tried summarily. The punishment of untouchability offences is being considerably enhanced and now both fine and imprisonment will be awarded for untouchability offences. For the first offence the minimum punishment will be one month's imprisonment and a fine of Rs. 100 and the maximum six months* imprisonment and a fine of Rs. 500. For the second offence, the minimum punishment is six months' imprisonment and a fine of Rs. 200 and the maximum, one year's imprisonment and Rs. 500 fine. For the third and subsequent offences, the punishment can range from one years' imprisonment with Rs. 500 fine to two years' imprisonment with Rs. 1,000 fine.

The significant characteristic of the present Bill is that public servants who wilfully neglect in the investigation of any offence punishable under this Act shall be deemed to have abetted an offence punishable under this Act. Persons convicted of untouchability offences shall be disqualified from contesting elections to Central and State Legislatures. The Probation of Offenders Act will not supply to untouchability offenders unless they are below the age of 14 years.

Thus the Bill will have a deterrent effect in curbing the commission of untouchability offences. The Bill also contemplates surveys and studies for determining the areas where untouchability is practised, the setting up of Committees for implementing the

/vet and the grant of adequate facilities to persons subjected to disabilities arising out of untouchability to enable them to avail of their rights.

Government is making every endeavour to uplift the Scheduled Castes and to ensure that the last vestiges of untouchability are completely eradicated from the country within the shortest possible time. Under the 20-point programme of the Prime Minister, various measures are being taken for the economic uplift of these down-trodden sections of the society. Most of them are agricultural labourers and petty artisans and for them, special measures for the grant of house-sites, agricultural lands, loans for settlement in trades, fixation of minimum wages and abolition of bonded labour are being undertaken so that their economic and social conditions improve and they are better able to assert their rights. The massive education programme for the Scheduled Castes both at the school stage as well as at the post-matric stage also helps them in improving their social and educational standards. The great strides achieved in filling posts in the country's public services at various levels have also contributed to raising the status of this community and also to giving them adequate strength to assert their rights. All these, together with the legal protection provided under the present Bill, will help in the complete eradication of this evil practice.

With these words, Sir, I commend the Bill for the consideration of the House.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKA-NATH MISRA) : Now, there are 12 speakers in all. Therefore, under compulsion the Chair will have to restrict each speaker to 10 minutes and not a minute beyond ten. So, in all we will take two hours for the speakers and 15 minutes for the reply of the hon. Minister so that by 5-15 punctually we finish this Bill and take up the other Bill. We must go according to the schedule. There will not be the slightest departure from the schedule. Mr. Bhola Prasad. 28 RSS/76—3

श्री भोला प्रसाद (बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस बिल पर अमल करने की क्या सुरत हो सकती है और उसके लिये कैसे गारन्टी की जा सकती है। अछूत अपराध कानून को कितना भी सक्त बना दिया जाय, लेकिन उस पर अमल करने की जो मशीनरी है वह मुख्य तौर से मौजूदा पुलिस प्रशासन पर निर्भर करती है। यह देखा जाता है कि मौजूदा पुलिस प्रशासन में ज्यादातर आफिसर्स ऐसे हैं जो कि उच्च वर्ग से आये हैं, सामन्ती वर्ग से आये हैं। या हरिजनों पर जो जुल्म करने वाले लोग हैं, समाज में उनके असर में रहने वाले लोग हैं, इन्हीं के द्वारा हरिजनों पर जुल्म होता है। हरिजनों को पुलिस के पास जाने में भी डर लगता है और अगर वह हिम्मत करके जाता भी है तो वहाँ उसको न्याय नहीं मिलता है, पुलिस का संरक्षण नहीं मिलता है। इसीलिये माननीय मंत्री जी ने अपने ब्यान में जिक्र किया है कि जब कि आज 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने का प्रोग्राम देश के सामने है और उस पर अमल करने के लिये कदम उठाया जा रहा है, तो इससे हरिजनों में बेशक एक उत्साह आया है, उनमें एक उभार आया है, अपने हक के लिये खड़े होने की शक्ति आज वह महसूस कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर एक तरफ गांव के गरीब खेत मजदूर जिनमें ज्यादातर हरिजन वर्ग से आते हैं उनमें उत्साह है, उभार है हक हासिल करने की तरफ और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को अमल में लाने की तरफ, तो दूसरी तरफ गांव के जो जमींदार हैं, भू-स्वामी हैं उनमें उतनी ही बोखलाहट है। आज वह हरिजनों के उभार को देखकर, उसकी जागृति को देखकर बोखलाये हुए हैं जैसे उनके कलेजे पर सांप लोट रहे हों। ऐसा सुरत में महाजनों, जमींदारों की ओर से हरिजनों के ऊपर हमले बढ़ रहे हैं। जब तक उनको यह गारन्टी नहीं दी जाती कि पुलिस का उनको संरक्षण दिया जायगा, अछूतों पर, हरिजनों पर जो जुल्म करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी, तब तक वह आज भी अपने इन्सानी हक और अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते उनके साथ तब तक न्याय नहीं होगा जब तक आप यह न कर दें कि ऐसे अपराधों के खिलाफ सक्ती

[श्री भोला प्रसाद]

से कार्यवाही की जायगी, न केवल उनका ट्रान्सफर किया जायगा, जरूरत पड़ने पर, बल्कि उनको सक्त सजा भी दी जायगी जिससे वह समझें कि आज हरिजनों के हक में जो कानून है, जो 20 सूत्री कार्यक्रम को अमल में लाने के लिए गरीबों के लिए जो कानून है उन पर मुस्तैदी से अमल नहीं करते हैं और उसके विपरीत जो शोषक वर्ग, हैं, जर्मीदार हैं सामन्ती भू-स्वामी हैं और जो जुल्म करने वाले हैं, अगर उनका पक्ष लेते हैं, उनका साथ देते हैं तो हम भी सजा के मुक्तभोगी होंगे और हमें सक्त से सक्त सजा मिलेगी। जब तक यह इन्फ्रेशन आज के प्रशासन में जो अफसर हैं, खास तौर पर पुलिस अफसर उनमें नहीं होगा तब तक न्याय उनके साथ नहीं होगा। आज तो इमरजेंसी में किनी का बहुत ज्यादा मान बढ़ गया है, और वह ज्यादा और भी कर्प्शन के शिकार हुए हैं, तो वह पुलिस का विभाग है। इसलिए हम सरकार से अर्ज करना चाहते हैं कि इस पर अलम करने के लिए आप गारन्टी करें और इसके लिए पुलिस अफसर जो इस पर अमल नहीं करते हैं, जो हरिजनों को संरक्षण नहीं देते हैं, जो 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिये खेत मजदूरों, हरिजनों और गरीबों को अधिकार दिलाने में उनका साथ नहीं देते हैं, उनके ऊपर सक्ती से कार्यवाही होगी।

साथ ही साथ सरकार दूसरी ऐसी भी 3 P.M. मशीनरी कायम करे जिसके बाद अगर पुलिस नहीं सुनती है, न्याय नहीं मिलता है तो वह हरिजन या गरीब अपनी मुश्किलें रख सके और उसके जरिये वह न्याय पा सके।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हरिजनों पर जुल्म बंद होना चाहिये। उनके ऊपर जो अत्याचार होता है वह बंद होना चाहिये। इसके लिये जरूरी है कि एक इंसान के जीने के लिये जिन जरूरी चीजों की आवश्यकता होती है, वे जरूरी चीजें उन्हें मिलें। इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिये। मिसाल के लिये पीने के पानी का सवाल है। हम गांवों-गांवों में देखते हैं कि खेत मजदूरों और हरिजनों के लिये अभी तक अपने कुएं नहीं बन सके हैं। उनके पीने के पानी के लिये कोई व्यवस्था नहीं है अलग से, इसलिये उनको सार्वजनिक कुओं पर या जो ऊँचे वर्ग के लोग हैं उनके कुओं

से पानी लेने के लिये जाना पड़ता है, खासतौर से उस वक्त जब कि हरिजन और गरीब लोग अपने हक के लिये उठ रहे हैं। उनमें उत्साह आया है इसलिये अपना सिर उठा कर चलना चाहते हैं। ऐसी सूरत में जब कि गांवों के भू-स्वामी, धनी वर्ग बौखलाए हुए हैं उनके लिये वहां से पानी लाना मुश्किल हो गया है। हम आखिरी दिन देखते हैं कि जब भी वे वहां से पानी लेने जाते हैं तो उन्हें एकदम रोक दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि तुम हमारे कुओं पर पानी पीने के लिये मत आओ। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। इसलिये हम यह अर्ज करता चाहते हैं कि सरकार इस बात की गारंटी दे कि जल्दी से जल्दी हरिजन बस्ती में पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी। हम चाहते हैं कि दूसरे कार्यक्रमों के साथ इस कार्यक्रम को भी शामिल कर लिया जाये। इसको लम्बा न खींचा जाये। सरकार को इस बात की गारंटी देनी चाहिये कि यह काम कुछ महीने के अंदर-अंदर हो जायगा।

इसी तरह से हरिजनों के आवास का सवाल है। यह सही है कि 20 सूत्री कार्यक्रमों के जरिये उनको घर के लिये जमीन देने की व्यवस्था की गई है। पहले भी ऐसा कानून बना था। 1948 में शाब्द यह कानून बना था कि जो हरिजन या गरीब किसी जमीन पर बसा हुआ है उसको वहीं पर बसने का अधिकार होगा। उसको वहां से हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन असलियत यह है कि 20-25 वर्ष बीत गये उस कानून पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। जहां कहीं भी यह सवाल पैदा हुआ वहीं पर से हरिजनों और गरीबों को, जो दूसरों की जमीनों पर बस गये थे, उनको निकाला गया। पिछले वर्षों से जब से हरिजनों की ओर से, गरीबों और खेत मजदूरों की ओर से देशव्यापी आन्दोलन छेड़ा गया तब से यह भी एक बड़ा सवाल बन कर देश के सामने आया और उसके बाद से अमल भी होना शुरू हुआ। हम अपने राज्य में देखते हैं कि 1969 से लेकर जून 1976 तक सब मिलाकर 7 लाख मजदूरों को आवास की जमीन पर अधिकार दिया गया है लेकिन अभी भी कई मजदूर, हरिजन ऐसे हैं जिन्हें इस आवास की जमीन पर अधिकार

नहीं मिला है जिस जमीन पर वे बसे हुए हैं। असलियत यह है कि जिस जमीन पर वे रह रहे हैं वह छोड़ी जमीन है और उसके अपने परिवार में वह खुद है, बेटा है, बेटा है, पतोहू है, मां-बहनें हैं। क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है और बाहर कहीं जा नहीं सकते इसलिए उनको वहाँ पर गुजारा करना पड़ता है। जिस प्रकार की जिन्दगी हरिजन लोग गाँवों में व्यतीत कर रहे हैं उसको ईसान की जिन्दगी नहीं कहा जा सकता है। हमारे बिहार के अन्दर जिसको मुशर का पखारा कहते हैं उस प्रकार की जिन्दगी हरिजन लोग व्यतीत कर रहे हैं। उनके रहने के लिए ठीक व्यवस्था नहीं है। उनके परिवार बहुत ही बुरी हालत में अपनी जिन्दगी बिताने हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उन लोगों को जमीन दी जाय। जब तक उनको अतिरिक्त जमीन नहीं दी जाएगी तब तक उनकी हालत में सुधार नहीं हो सकता है। इस बारे में पिछले दिनों जब हिसाब लगाया गया तो पता चला कि जून के महीने तक 65 लाख लोगों को बसने की जमीन दी जा चुकी है। बिहार में जिन लोगों को जमीन दी गई उनकी संख्या 7 लाख है और सारे देश में जिन लोगों को बास की जमीन दी गई है उनकी संख्या 65 लाख बताई जाती है। इसमें पुराने और नये सभी लोग शामिल हैं। मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को बास की जमीन देने की आवश्यकता है। जिन लोगों के परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ गई है उनको अतिरिक्त जमीन देने की आवश्यकता है। अभी स्थिति यह है कि पहले तो काफी दिनों तक हरिजनों के लिए जमीन सेंशन ही नहीं की जाती है और जब सेंशन होती भी है तो दूसरे गाँव या प्रखण्ड में उनको जमीन दे दी जाती है। वहाँ पर वे लोग बस नहीं सकते हैं। मुझे मालूम है कि हरिजनों को इस तरह की जमीन अलाट की गई है जिसमें वे लोग बस नहीं सकते हैं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि उन लोगों को ऐसी भूमि अलाट की जाय जहाँ पर वे लोग आसानी से बस सकें और अपनी जिन्दगी ठीक प्रकार से बसर कर सकें।

इसके साथ-साथ मैं बंधुवा मजदूरों की बात भी कहना चाहता हूँ क्योंकि इनमें ज्यादातर लोग हरिजन होते हैं। कहा जाता है कि पूरे देश में 58 हजार 4 सौ बंधुवा मजदूरों को मुक्त किया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनकी संख्या और भी बड़े पैमाने पर है। हमारी बिहार की सरकार तो कहती है कि उनके यहाँ सिर्फ पलामू जिले के कुछ प्रखण्डों को छोड़कर और कहीं भी बंधुवा मजदूर नहीं हैं। यद्यपि इस संबंध में केन्द्रीय कानून बना हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ही बंधुवा मजदूर माना जाता है। जो भी बंधुवा मजदूर हैं उनमें ज्यादातर किसी न किसी रूप में हरिजन हैं। उनकी मुक्ति के लिए जब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं की जाती है जब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है उनके लिए कर्ज देने जल्द से जल्द कोई ठोस योजना बनाई जाये। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो भी एक्ट आप बनाये या उनके लिए प्रशासनिक व्यवस्था करें, जब तक आप उन पर ठीक प्रकार से अमल नहीं करेंगे तब तक हरिजनों की हालत में सुधार नहीं हो सकता है। सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा बल्कि हरिजनों की भलाई के लिए हमें जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए।

SHRI YOGENDRA MAKWANA (Gujarat) : Mr. Vice-Chairman, Sir...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA) : Kindly be brief.

SHRI YOGENDRA MAKWANA : Sir, I will confine myself only to the Bill, I will not go into all the other details.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support and welcome this Bill introduced by the Home Minister. I congratulate the Home Minister for introducing such a revolutionary Bill. As I described it, it is really a revolutionary Bill in a way, because it has so many provisions which enable an untouchable to get those persons prosecuted who observe untouchability and it also enables him to protect himself against

[Shri Yogendia Makwana] the possibilities arising out of untouchability.

Sir, first of all, I will like to refer to the title of the Bill. The title is changed and instead of "practising of untouchability", the words "preaching and practising of untouchability" have been used. Sir, those words look very simple, but they have a great effect. The word "preaching" is inserted before the word "practising".

The practice of untouchability was an offence in the principal Act. Now, preaching of untouchability also becomes an offence under this Bill. In the previous session and before that also, I have often remarked in this House against the religious heads of this country. Sometimes they make derogatory remarks against the Scheduled Castes. Sometimes they have preached untouchability. With the insertion of these words, Shankracharya of Puri and Doongri Maharaj or any other religious heads who were preaching untouchability will not be able to do it. They can be prosecuted under the present law. Sir, in sub-section (1) of section 1, the words "the Untouchability (Offences) Act" have been substituted by the words "the Protection of Civil Rights Act". This is also an important change in the principal Act because the civil rights of the so-called untouchables were not honoured by some of the people of this country. I do not mean all the people of this country. But some people who are orthodox and reactionary have been always attacking the untouchables.

Sir, another salient feature of the Bill is to be found in section 3(iii) of the Bill. Whereas the minimum punishment was fixed for one month or fine under the principal Act, the word "or" has been substituted by the words "and also" in the new Bill. This is a very significant change because fine has also to be paid over and above the punishment of imprisonment. It will become a sort of deterrent to those who are observing untouchability. As I have said in the beginning, mostly the religious heads are responsible for untouchability. As the change in the title is an

important thing, so also Explanation II after Explanation I in section 7 is a very important explanation. It reads like this :

"Explanation 11.—For the purposes of clause (c), a person shall be deemed to incite or encourage the practice of "untouchability"—

(i) if he, directly or indirectly, preaches untouchability or its practice in any form; or

(ii) if he justifies, whether on historical, philosophical or religious grounds or on the ground of any tradition of the caste system or on any other ground, the practice of "untouchability" in any form."

Sir, these words are very important because all the religious heads have been describing untouchability as a part of religion as it is given in the religious books and sometimes they give some historical background to it. In the present day and in the present society, that background has been lost. Nowadays, the accepted principle is that every human being is equal. It has become an accepted universal principle. Therefore, such outdated discourses by the religious leaders should be banned.

Sir, there is also a provision under section 7(a) which gives an opportunity for untouchables to perform other occupations. In small villages, even the educated persons were asked to take the night soil on their head and to scavenge the streets. Sir, with this insertion of section 7(a), there is a ban on it. So, it will be a very good provision in the principal Act. Then, Sir, there is an insertion of an explanation at the end of Section 10. This is a most important explanation which is now inserted in the principal Act. It reads like this : "A public servant who wilfully neglects the investigation of any offence punishable under this Act shall be deemed to have abetted an offence punishable under this Act."

Sir, in most of the cases of atrocities, we have seen that the public servants have

neglected their duty at the time of investigation. Even the HRs are changed at many places, and the public servants, specially the police officers, instead of investigating and prosecuting the offender, help the criminals. And the history shows that even one person was not punished during these 25 years. Now, Sir, with the addition of this explanation to the principal Act, I hope, there will be a good check on the police officers who will try to play mischief and evade their responsibility. *(Time bell rings)* I will complete within a few minutes, Sir. Sir, I described this Bill as revolutionary and I must justify why I called it a revolutionary Bill, and I congratulate the Home Minister. He should also recommend to give me some more minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA): All of us should be precise and concise also.

SHRI YOGENDRA MAXWANA: Sir, this Bill is really a very good Bill. Sir, so many provisions are included here and I cannot go into details. As you say, Sir, the time is limited I will throw some light on some of the general aspects of the Bill. There was a very good provision suggested by the Joint Select Committee under Explanation 2, after Section 10, which is now deleted. I do not know why it is deleted. The Explanation reads like this : "Any appointing authority, in relation to any service or post in connection with the affairs of, (a) the Union or any State Government, (b) the corporation or undertaking, owned or controlled by the Central Government or the State Government or by both, (c) any authority or body established by any Central, State or provincial Act, (d) any local authority, who show any negligence in giving effect to the orders of the appropriate authority relating to the reservation of posts for the employment of the members of the Scheduled Castes shall be deemed to have abetted an offence punishable under this Act." Sir, I would request the hon. Minister to accept this Explanation even now at this stage. I would like to invite his attention and the

attention of the House to the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This is the latest report for the year 1973-74 in which he has mentioned about recruitment to the Central Government services and other services in different States. I will not read the figures because they are very negligible. But I will read the remarks of the Commissioner. He says : 'The figures in this Table reveal that the representation of Scheduled Castes in these services is still far from satisfactory. The position regarding Scheduled Tribes is much worse.' Sir, these are the remarks made by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Why are these remarks

there ? It is only because the bureaucrats, the Government officers, who are the recruiting officers who sit in the committees do not like and do not observe the provisions relating to reservations. Recently, Sir, we had an occasion to examine the Delhi authority where some rules are framed. But they have recruited their sons and daughters and their relatives only and the percentage of recruitment of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is not maintained. It is not only negligible but in some cases it is not at all there. No Scheduled Caste man is taken in the Delhi Administration authority.

Sir, I appreciate this Bill very much because I have also had occasions, as a political leader of my district, to suffer so many attacks by high caste Hindus in the course of elections and at several other times too. In the course of elections the Harijans became the victims particularly because they favour the Government or some party, especially the Congress Party which works for the upliftment of the Harijans and down-trodden people. That is why the Harijans who support the Congress Party in the interior parts are attacked. Several times in this House also. Sir, if you remember, the Prime Minister herself has given two examples of my own State and of my own district. In the course of the last elections, in a Christian locality in a village in Kaira District the houses of a large number of Christians, who voted for

[Shri Yogendra Makwana.] the Congress, were put on fire and several families were burnt.

(Time Bell rings)

In the case of election of my wife we were attacked at so many places and we were not allowed to enter five villages and we lost the election only because of these things. Therefore, I say that this Bill is a revolutionary Bill and I heartily congratulate the Home Minister and the Prime Minister for introducing this Bill. It will be a red letter day in the history of India when it becomes an Act. With these words, Sir, I end my speech.

श्री प्रकाशचौर शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : उपसभा-पति जी, सौभाग्य से मेरा जीवन ऐसे संगठन से सम्बन्धित रहा है जो छुआछूत, जाति-पाति, ऊँच-नीच की भावनाओं से संघर्ष करता आया है और इसीलिए जब सरकार इस प्रकार का विधेयक लाई है तो मुझे उस पर संतोष भी होता है और इसके लिए प्रसन्नता भी व्यक्त करना चाहता हूँ। परन्तु साथ ही साथ मैं कुछ विरोधाभास भी देख रहा हूँ। एक ओर तो सरकार असुष्यता निवारण करने के लिए विधेयक लाई और दूसरी ओर कुछ इस प्रकार की सुविधाएँ दे रही है जिससे असुष्यता को और बल मिले ऊदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँगा कि पहले कहा गया था कि हरिजनों के लिए पृथक छात्रावासों की स्थापना की जा रही है। मेरा कहना यह है कि पृथक छात्रावास हरिजनों के लिए बनाये जायेंगे तो यह असुष्यता का भाव समाज के अन्दर बराबर बना रहेगा। हमारा कहना यह है कि छात्रावास सबके लिए एक साथ होना चाहिए। उसमें हरिजन का छात्र भी रहे, सर्वर्ण का छात्र भी रहे। अगर इस तरह से छात्रावास पृथक-पृथक कर देंगे तो असुष्यता और छुआछूत की भावना जो हम मिटाना चाहते हैं और जिसके लिए बंड देने की व्यवस्था इस विधेयक के माध्यम से हम कर रहे हैं वह मिट नहीं पायेगी। मैं चाहता यह हूँ कि इस बात पर गंभीरता से सोचा जाये और इस प्रकार से अलग छात्रावासों की व्यवस्था हरिजनों के लिये न हो ? उनके लिये व्यवस्था अवश्य हो,

लेकिन उसमें सब लोग रहें और जो दूसरे छात्रावास हैं उनमें भी हरिजन विद्यार्थी जाकर रहे और वहाँ सबका रहन-सहन खान पान, सब कुछ एक साथ हो, उनका पठन पाठन एक साथ हो। ऐसा होने पर ही हम असुष्यता के विष से मुक्ति पा सकेंगे।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : अभी भी हरिजन छात्रावासों में दस परसेंट लेते हैं, लेकिन कोई छात्र नहीं। शास्त्री जी, आप उनका प्रतिशत बढ़ायें ताकि वह छात्रालयों में आयें।

श्री प्रकाशचौर शास्त्री : मैं मकवाणा जी को कहना चाहता हूँ कि मैं तो इस प्रतिशत वाली बात को ही समाप्त करना चाहता हूँ। दस प्रतिशत या पचास प्रतिशत की कोई बात छात्रावासों में नहीं होनी चाहिए। छात्रावासों में सर्वर्ण विद्यार्थी भी रहे और हरिजन भी, उनमें प्रतिशत की बात रहनी ही नहीं चाहिए। अगर आप वहाँ प्रतिशत की बात रखते हैं हरिजनों के लिये तो उससे यह असुष्यता बढ़ेगी, घटेगी नहीं। आप इस बात को थोड़ा सोचिये और अगर मेरी इस बात में कोई बल है तो उस पर फिर विचार करिये।

दूसरी बात जो हरिजन शताब्दियों से पद-दलित रहे हैं और सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित रहे हैं उनके लिये सरकार ने रिजर्वेशन की व्यवस्था की है। जो रिजर्वेशन उनको दिया गया है वह उनकी संख्या के अनुपात से है। मेरी अपनी इच्छा है कि उससे भी अधिक स्थान उनको सरकारी नौकरियों में और हमारे स्थानों में मिलें, लेकिन यह स्थान उनको हरिजन कहकर न दिये जायें। जब हरिजन कहकर किसी को कोई सुविधा दी जाती है तो उस पर एक प्रमाण पत्र लगा दिया जाता है। यह व्यवस्था मैं समझता हूँ कि लम्बी चलने वाली नहीं है। मैं सरकार से भी ज्यादा अपने हरिजन भाईयों के सामने यह बात विचार के लिये रखना चाहता हूँ कि अगर इस का कोई और विकल्प हो सकता है तो हमें सोचना चाहिए। जब हरिजन कह कर हम किसी को कोई सुविधा देते हैं तो उसके साथ हम एक प्रमाण पत्र लगा देते हैं। हमको सामाजिक एकस्यता का निर्माण करना है। चाहे नौकरियाँ हों, विद्यालय हों, स्कूल हों, छात्रावास हों या

जाँझियरी हों, सबमें सबका समान रूप से प्रवेश होता चाहिए। नीति के तौर पर आप पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो पद-दलित हैं, उनके लिये जो अनुपात आप ने रखा है उसको आप बढ़ा दें, लेकिन एक प्रमाण पत्र लगा कर उसको आप मत बढ़ाइयें वरना यह होता है कि जो एक रेखा खिंची हुई थी मनों में, ऊपर से तो वह मिट जायेगी, लेकिन मनों के अन्दर वह रेखा मिटेगी नहीं। इसलिये हमें इस दृष्टि से इस पर विचार करना चाहिए।

तीसरी बात, सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि जो हमारे हरिजन भाई हैं उनके लिये आजकल जमीन देने का काम किया जा रहा है। लेकिन उपसभापति जी, हमारे देश में जमीन सीमित है और आज भी गांवों में मैं देखता हूँ कि जितने लोग हैं, जितने हरिजन हैं उन सबकी जमीन मिली नहीं। अब कारण क्या है? कारण यह है कि जमीन तो उतनी मिलेगी कि जितनी खाली होगी या सीमा से अधिक होगी। इसलिये उनकी भूख तो जग गयी, और उनको भोजन मिला नहीं और इसलिये जिनको जमीन नहीं मिल पायी है वे भूख के मूखे हैं। इसके लिये सरकार को यह करना चाहिए कि भूमि के बजाव कुछ दूध देने वाले पशु हरिजन परिवारों को दे दिये जायें। किसी को भैंस दे दी जाय, किसी को गाय दे दी जायें। उसका परिणाम यह होगा कि एक आदमी जिस को दो एकड़ जमीन आप दैते हैं उस को पहले बैल खरीदने पड़ते हैं, फिर हल का इंतजाम करना पड़ता है, लेकिन अगर उस के स्थान पर उसके पास दूध देने वाले पशु हों और एक दिन में आवश्यकता से अधिक दो सेर दूध भी वह पैदा कर लेता हो तो उस से उसको आठ या दस रुपये रोज की आय हो जाती है। उस से वह बहुत आसानी से अपने परिवार का निर्वाह कर सकता है। तो जिनको भूमि नहीं मिल सकी है उनके लिये मेरा कहना है गृह मंत्री जी देखें और कृषि मंत्रालय से मिल कर किसी ऐसी योजना पर विचार करें कि जिस में दूध देने वाले पशु ऐसे परिवारों को दिये जायें और उस के बाद उनकी संख्या बढ़ाते चले जायें। बँक उनको ऋण दे। ऐसा होने से श्वेत क्रान्ति की योजना को भी बल मिलेगा और उनकी हालत में सुधार भी हो सकेगा।

श्री इब्राहीम कलानिया (गुजरात) : हरिजनों का दूध आप लेंगे ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : दिल्ली में जितना दूध आता है उसमें मोहर नहीं लगी होती कि वह हरिजन परिवार के यहां का दूध है या सवर्ण परिवार का। दिल्ली मिल्क स्कीम में तो सारा दूध एक जगह इकट्ठा हो जाता है और हमारे यहां देहातों में भी अब यह भावना भी नहीं रही। गुजरात में ऐसा हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और हरियाणा में अब यह बात नहीं है। दूध हरिजन परिवार का है या सवर्ण परिवार का है, यह शायद गुजरात में होता होगा। वहां इस प्रकार की दुर्बलता होगी, लेकिन यहां इस प्रकार की दुर्बलता नहीं है। अगर है तो इस तरह के कानून उसमें मदद करेंगे।

श्री ओम् मेहता : यहां दूध की क्या बात है, खून भी एक ही है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : दूध के बाद ही तो खून बनेता है, वह भी एक ही है। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि आज गृह मंत्रालय इस बात के ऊपर विचार करे, इस तरह का एक बिल हम पहले पास कर चुके हैं जिसमें कुछ जातियों के क्षेत्र आपने बढ़ाये हैं। एक विधेयक हम यह पास करने जा रहे हैं कि अस्पृश्यता को हम कानून के द्वारा समाप्त करना चाहते हैं और समाज में भी उस तरह का भेदभाव समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन हरिजन के नाम पर जो सुविधायें मिल रही हैं, मेरा अपना अनुमान है, गुजरात के हमारे मित्र बतायेंगे और भी राज्यों के लोग बतायेंगे कि हरिजनों की सुविधायें भी, गांवों में मैंने देखा है कि कुछ परिवार तक सीमित हैं। उनमें पढ़े लिखे लोग और जो समृद्ध परिवार हैं वह उसका लाभ उठा रहे हैं। सामान्य हरिजन इन सुविधाओं से वंचित हैं। होना यह चाहिए कि जो आदमी सरकारी सविस में मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर हो गया है जिसकी आय 500 रुपए से अधिक है वह इससे हटा दिया जाए। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको यह सुविधा मिलनी चाहिए। जो गरीब हैं, जो भी हरिजन या इस प्रकार का वर्ग है वह बेचारा आज भी नहीं जानता कि सरकार की क्या सुविधायें उनको मिलनी चाहिए। उन तक यह बात

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

पहुंच नहीं पाती। मैं चाहता हूँ कि जरा संभारता से इस बात को देखा जाए कि किस तरह से इसका लाभ उन लोगों को पहुँचाया जा सकता है।

एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि इस काम में आप समाज-सेवी संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त करें। जैसे रामकृष्ण मिशन के लोग हैं या स्वामी विवेकानन्द सोसायटी के लोग हैं या आर्य समाज के लोग हैं और दूसरे भी इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने सैद्धांतिक दृष्टि से इस को उस समय से अपने हाथ में लिया है जब यह देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। उन्होंने प्रारम्भ से ही इसको समाज के लिए एक विषय मान कर कार्य किया है। इस तरह के संगठनों का सहयोग भी सरकार को प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि इस विषय से देश सदा के लिए मुक्त हो जाए।

अन्तिम बात जिसको मैं कह कर बैठ जाना चाहता हूँ वह यह है कि मेरा यह हार्दिक विश्वास है कि अगर इस देश से छुआछूत की बीमारी को मिटाना है तो यह तब तक मिट नहीं सकती जब तक सवर्ण जाति के लोग अपने नामों से जातिवाचक शब्दों को लगाना नहीं छोड़ेंगे। नामों के साथ जातिवाचक शब्दों के लगने से एक रेखा खिंची हुई है। हमी भी मैं आल इंडिया रेडियो सुनता हूँ तो अनाउंस करने वाले लोगों के नामों के साथ भी जातिवाचक शब्द लगे रहते हैं, फिर जिसका ये अनाउंस करते हैं उनके साथ भी जातिवाचक शब्द लगते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस 25 सूत्री कार्यक्रम में मैंने देखा कि जातिपात का विरोध करने के लिए भी एक सूत्र उसमें दिया गया है। लेकिन उस सूत्र की व्याख्या इतनी अवश्य कर दी जाए कि इस देश से जातिपात तब समाप्त होगी जब लोग अपने नामों के साथ जातिपात लगाना छोड़ेंगे। पहले कदम के रूप में इतना तो कम से कम काम करें, आप शिक्षा मंत्रालय को आर्डर दीजिए कि पहली और नर्सरी क्लासेज में जो छोटे-छोटे बच्चे दाखिल होते हैं उनके नाम के साथ जाति-सूचक शब्द नहीं लगाया जाएगा। बचपन से यह जाति-सूचक शब्द लग कर उनके मन में जाति का मोह जगाता है और बड़े होकर वह जाति-सूचक शब्द उनके नाम का एक अंग बन जाता है।

श्री एन० एच० कुम्भारे (महाराष्ट्र) : आपने सिर्फ एक पहलू कह दिया है। दूसरे पहलू को आपने छोड़ दिया है। हम जाति का नाम नहीं रखेंगे तो सामने वाला आदमी यह जानने की कोशिश करेगा कि यह कौन जाति का है। जब पता लगेगा कि शैड्यूल्ड कास्ट का है तो उसके मस्तिष्क के कड़े उसको काम नहीं करने देंगे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरी बात को मेरे मित्र ने सुना नहीं, मैं यही कह रहा था। हमारे समाज में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रोत्साहन मिले, जाति के नाम पर किसी से किसी की आत्मीयता प्रकट होती हो या स्नेह का संबंध पैदा हो, ऐसी भावनाओं के अंकुर जहाँ भी और जिस तरह से भी पैदा होते हैं वह सारे के सारे नष्ट किये जाने चाहिए। मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे पक्ष की भी बात कर रहा हूँ।

(Time Bell rings)

श्रीमन्, मुझे इतना ही कहना है।

उपसभाध्यक्ष (श्री लोकनाथ मिश्र) : श्री वेश-म्पायन। मेहरबानी करके 10 मिनट ही लीजिए।

5/7/1976

SHRI S. K. VAISHAMPAYEN (Maharashtra) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I wish to extend my wholehearted support to this Bill. The Bill has been brought forward after a very careful consideration by the Joint Committee of the two Houses. At the same time, I consider that this Bill is a little belated. But it is a step in the right direction to end the scourge of untouchability. The Bill removes all the vagueness that was there in the earlier Act. The clauses have been so framed that there is some definiteness in regard to the action to be taken. It also lays a firm hand on those who would act against the spirit of the Constitution. I support the provision made in this Bill particularly for imposing collective fines. As I see it, UH-touchability has assumed a very acute form during the last three to four years. There are social boycotts, burning of huts of Harijans and even murders. So, this provision of collective fines is really a provision which will go a long way to see that this scourge is ended. The provisions are

certainly very stringent but there should also be other measures which must be taken by the Government as such. I should say that the hon. Home Minister should issue directives to all the State Governments to have a special cell in their respective Home Departments.

Secondly, there should be vigilance committees at district level and they should have Member of Parliament as Chairman and the Collector as the Secretary of that committee. It is because I have the experience of such a vigilance committee. We have tried to see that offences of this nature which come under untouchability have become less.

Thirdly, I would like to say that this social evil is still much deep-rooted. According to whatever information I have, I would like to point out that the extent of atrocities committed during these years has increased. I would like to give figures of atrocities committed during the years 1972, 1973 and 1974 and this information has been given by the Home Ministry in a reply given in the Rajya Sabha on 27th February, 1975. I will only quote a few figures from two or three States. I will take my State first. In Maharashtra during 1972, 124 atrocities have been committed. In 1973 the number was 223 and in 1974 it was 277. This shows that the number has gone up year by year. Similarly, in Gujarat the number in 1972 is 246, in 1973 it is 248 and in 1974 it is 352. In Uttar Pradesh the figure is still rising high. The number in 1972 is 567, in 1973 it is 1179 and in 1974 it is 1178. So, this is still a deep-rooted malady and we will have to take other measures along with these stringent provisions to combat the menace. We shall have to undertake intensive promotional activity also. I will suggest that incentives must be given to those villages who have freed themselves of this particular malady of untouchability. There are a number of villages who have declared that there is no untouchability in their villages. All the communities have come together in gram sabhas and declared so. We should give some incentives to such villages. Similarly, there are some social

workers, not of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who are working in the field for the welfare of Harijans, for ending untouchability. They must also be given some special awards by the State Governments. Then, there are provisions made in our State. We have Zila Parishads. There are provisions for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But our experience is that these provisions are not spent. Not only they are not spent but the provisions are transferred to some other measures which do not help the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I have figures from Maharashtra which go to show that 10 Zila Parishads, despite the provision being there for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, have spent zero per cent. Seven Zila Parishads have spent one per cent, four have spent one to five per cent and three have spent five to ten per cent of the provisions that were made in the Zila Parishad budgets. So, this aspect also should be gone into in each State and a directive should be issued by the Home Ministry that whatever provisions are made for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be spent on their welfare. Rather I would suggest, Sir, that these provisions should be earmarked and the allocations should not be transferred to any other department as such.

Then the question of untouchability has taken a new dimension and that dimension has an economic aspect also. Under the 20-point economic programme we are now helping the economically weaker sections, and amongst the economically weaker sections the percentage of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is as high as 50 per cent at some places and even 70 per cent at some other places because they are all landless labourers. Naturally because of the measures which are there under the 20-point economic programme, those who are going to benefit under them are coming into clash with the landed, vested interests in the rural areas. The question of untouchability has taken a new dimension and therefore it is necessary that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and their leaders must organise a massive

[Shri S. K. Vaishampayan.] movement by forming a united front with the other economically weaker sections so that all the economic injustices that are being done to these poorer sections in the rural areas are ended. And if all these measures succeed—the measures under this Bill, other promotional measures and also a movement by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and their leaders with a common united front with the other economically weaker sections in the rural areas—the day of deliveiance is not far off. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKA-NATH MISRA) : Thank you, thank you.

श्री रोशन लाल (हिमाचल प्रदेश) : जनाब वाइस-चैयरमैन साहब, छुआछूत को ज़ुर्म करार देने पर मैं श्री श्रीम मेहता साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं प्राइम मिनिस्टर साहिब को भी मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने यह इस्टिक् स्टेप उठा कर इन गरीब लोगों को जो सदियों से मुतासर थे, राहत दिलाई है। लेकिन आज सोचने वाली बात यह है कि छुआछूत को हम सिर्फ कानून से दूर नहीं कर सकते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि लोगों के दिलो-दिमाग को तबदील किया जाय। मैं समझता हूँ कि दिलो-दिमाग की तबदीली का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसा श्री शास्त्री जी ने दो तीन मुझाव दिये हैं, मैं भी उनकी पूरी तारीफ करता हूँ कि हर एक आदमी को अपने नाम के आगे से पांड्या, शर्मा वगैरह कास्ट्स संबंधी बातों को हटा देना चाहिए। कोई किस जात का है, यह बात नाम के साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ कह देने से यह मसला हल नहीं हो सकता है। इसके लिए लोगों के दिलों को टटोलने की जरूरत है। जब तक हमारे दिल साफ नहीं हो जाते हैं, तब तक मसला हल नहीं हो सकता है और न ही हमें इसमें कामयाबी मिल सकती है।

इस बारे में मुकत्सर तौर पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी हाल के जमाने में हम तीन दौरों से गुजरे हैं। एक दौर तो गांधी जी का आया और फिर उसके बाद पं० जवाहरलाल नेहरू जी का दौर आया और आज इंदिरा जी का जो दौर चल रहा है उसको मैं इससे पहले के दौर से बा-

वस्ता करता हूँ। आप जानते हैं कि गांधी जी अपनी जिन्दगी भर जांत-पांत, काम्युनेलिज्म और कास्टिज्म बरबैरिस्म सिस्टम के खिलाफ सारे हिन्दुस्तान में जहोजहूद करते रहे। आखिर में उन्होंने इसके लिए अपनी जिन्दगी भी कुर्बान कर दी। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जमाना आया। उन्होंने समाज में सब को एकसा तरजीह देने की कोशिश की। आप जानते हैं कि गांधी जी ने पंडित नेहरू को अपना जाँ नशीन बनाया और देश की बागडोर उनके हाथों में सौंप दी। पंडित नेहरू ने हमारे मुल्क के लिए एक आईन बनाया जो 26 जनवरी, 1950 को कौम के सामने आया। उस वक्त यह कहा गया कि हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, जिसमें सब को बराबर के हक होंगे और हम इस आईन पर अमल करेंगे। जिसकी बुनियाद कोआपरेटिव बेसिस पर होगी, जिसमें हर शक्स् को बिना किसी लिहाज—मजहब, अक्कीदा, ख्यालत, जांत-पांत, रंगों के नस्ल—के सब को एक से हकूक होंगे, अगरचे हर कसो नाकस बराबर का होगा, उस आईन के अन्दर गारंटी दी गई, लेकिन बदकिस्मती से साढ़े 26 साल गुजर गये और हम उस पाये तक्कील तक नहीं पहुंच पाये जिनके लिये काबले-फरवर काबिल नेता चाहे गांधी जो हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, ने एहतिमाम किया। अब इस जमाने के दौर के अन्दर मुल्क की समाजी इक्वलिटी हालत बेहतर करने के लिये तजवीज की, लेकिन जो टोडी लोग, जनसंघी या फिरकेवाराना लोग थे, उन्होंने उनकी मुखालिफत की। मैं पिछले 5-6 सालों के दौरान भी इस हाउस में था, इस हाउस में शोरो-शराबा और गाली-गलौज पर लोग उतर आते थे। यह इस हाउस की ही तौहीन नहीं थी बल्कि उससे देश का बकार नीचा होता था। चुनावे हमने देखा कि इन्दिरा जी ने जो हमारे पुराने रस्मो-रिवाज चले आ रहे थे, इस देश में, उनको बदलने के लिये कदम उठाया। यह देश कुर्बानियों का देश है। यहाँ अजीम कुर्बानियाँ दीं और त्याग किये। जब जब जुल्म व तगदुल व बरबरियत का दौरदौरा होता है तो कोई न कोई महान शक्ति हनुमा होती है। चुनावे इस मौजूदा दौर में जब धर्म और अंधम की लड़ाई शुरू हुई, इन्सानियत के लिये कोई भूत बन कर खतरा पैदा हुआ तो इन्सानियत के लिये कोई फई रखने के लिये कोई अजीम शक्ति हनुमा

होती है। चुनावों श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन तमाम जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लिया और इस देश का जो जमहूरी निजाम था उसकी कद्रों को पामाल नहीं होने दिया, बल्कि उनको जमहूरी जायतों और कायदों के बरूपकार लाकर चन्द एक ग्रहम तरसीम शुदा एक दामाद इन में इस ग्रहम तरसीमात के जरिए हाउस में लाई।

इस देश में कई हजार वर्ष पहले चाहे वह बैरुनी ठांचे और बैरुनी मदाखलत का अमर हो, बाहर के लोग आये और उन्होंने हमारे तमाम मजहब और तहजीब को बरबाद किया, चाहे वह यहां के लोगों की खुदगर्जी की बजह से हुआ हो।

(Time Bell rings)

अपने चंद अल्फाजों के साथ मैं खत्म करता हूं।

इसका अमली बुनियादी कारण हमारी गुलामी थी। हम चाहे राजाओं के गुलाम थे और चाहे किसी और बैरुनी ताकत के गुलाम थे। एक ओर मैं अर्ज करना चाहता हूं, फारसी में है:

गर औरोज रागोयल शबअसतई
बबायेद गुप्त ईनख महाप्रवी

जब बादशाह अपने दरबारियों को दिन को रात कहता है तो सब दरबारी एक जवान होकर कहते थे ऐ आली जहांपनाह (आसमान की तरफ लंगरी उठा कर) वह मामने ऊपर चांद और तारे नजर आ रहे हैं। हमारे देश की यह हालत रही कि यहां पर चार आदमी डोमिनेट करते रहे इस देश को— एक गुजारी और भण्डारी, एक मंत्री और दूसरा संतरी। गुजारी पण्डित लोग जो उन्होंने ऐसा आईन बनाया कि जिसने सारी कोम की मुख्तलिफ जंगीरों में जकड़ डाला कि उससे बाहर कोई निकलने न पाए। भण्डारी वे थे जो बाहर से खेती का सामान, खाने का सामान राजा के दरबार में आता था, उसको तकसीम करते थे और मंत्री वे थे जिन्होंने अपनी लड़कियों के रिश्ते उन राजाओं से किए। उनमें दूसरे जो लोग थे नानेदार, रिश्तेदार, वे संतरी बन गए। सारे चार लोग डोमिनेट करने लगे और जो खेत मजदूर था वह उसी खानदान से चला आता रहा जो खेती का काम करता था। वह इतना पसमांदा हो गया कि उसे आईनी, मयाशी और सभाजी और अखलाकी कदमों

से महसूस रखा गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह इकतसादी तौर पर आज भी पसमांदा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं सही समय में एक सही ईसाफ लाना चाहते हैं तो आपको जैसे प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने निहायत जरूरत-मंदाना, निहायत आला इकदामात निहायत समझदारी और आला टैक्नीक के साथ, जमहूरी कद्रों को साथ रख कर ये कदम उठाए हैं उसी तरह से आनाम को तब्दील करने के लिए भी कुछ कदम, नए कदम, उठाने पड़ेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री लोकनाथ मिश्र) : अब बैठ जाइए। श्री विश्वम्भर नाथ पांडे।

श्री रोशन लाल : तो मेरा कहना है कि . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री लोकनाथ मिश्र) : 12 मिनट आपके हो गए हैं। दूसरों को भी बोलना है।

श्री रोशन लाल : फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि महज कानून बनाने से नहीं होगा। अगर आपने आईन मुरतब कर दिया और ममल लिया कि हमने सो कामयाबी हासिल कर ली तो मैं समझता हूं यह कामयाबी नहीं होगी। जमाना जो है उसमें अब उनका पैमाना मत्र लवरेज हो चुका है, वे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। समाज ऐसी तब्दीलियां लाना चाहता है और अगर वे तब्दीलियां नहीं की गई तो समाज से कानून के बंधन टूट जाने हैं और उससे इन्सान एक खूबार अजदा अकल अक्लि-यार कर लेता है। इसलिए अगर जमहूरियत को कायम रखना है, समाज को कायम रखना है, तो आपको जमहूरी तरीके के साथ इस कानून को इम्प्लीमेंट कराने में पूरा और सरकार को देना चाहिए।

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे (नाम-निर्देशित) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह जो बिल हाउस के मामले पेश है मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन बड़ी अदब के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि जब तक इस मामले का कोई बुनियादी हल नहीं निकालते तब तक यह ममला हल नहीं हो सकता। मैं थोड़ी सी मिसालें देकर इस चीज को साफ करना चाहूंगा। जब गांधी जी ने हरिजन आंदोलन शुरू किया तो बहुत से भाइयों के दिलों में यह बात आई कि उन्हें खान-पान के अगड़े

[श्री विश्वम्भर नाथ पांडे]

तोड़ने चाहिए और इन बंधनों से ऊपर उठना चाहिए। हरिजन क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे थे उन में जस्टिस शंकर सरन भी एक थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे; उनके मन में ऐसा आया कि हमें खान-पान के झगड़े तोड़ देने चाहिए। मुझ से उन्होंने कहा तो मैंने कहा आप ठीक कह रहे हैं। एक दावत उन्होंने कुबूल की मेहतर भाई के यहां लड़की की शादी की। उन्होंने यह कहा कि हम पंगत के साथ बैठ कर खाएंगे। मैंने कहा, मैं तो पहले से ही खाता आ रहा था, आप में नया जोश है, जरूर पंगत के साथ आप खाएंगे। पंगत में बैठ कर खाया हम लोगों ने। उनको बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि उन्होंने एक पुण्य कार्य किया और हिन्दू धर्म के कलंक को—जहां तक उनका व्यक्तिगत सम्बन्ध था—उन्होंने धो डाला। दूसरी मर्तबा फिर एक दावत मिली एक मेहतर भाई के यहां। वहां गये, उन्होंने बहुत कोशिश की कि पंगत के साथ बैठ कर खिलाया जाय लेकिन वे लोग टालते रहे। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या बात है, ये लोग हमको पंगत में क्यों नहीं खिलाते। दरियापन करने के बाद मैंने उनसे कहा कि इनको यह शिकायत है कि आपने बांदा टाट बिरादरी वालों की पंगत में खा लिया, इसलिए हेला टाट वाले आपको कैसे अपनी पंगत में खिला सकते हैं। छुआछूत का यह एक अटूट सिलसिला है। जैसा भाई प्रकाशवीर शास्त्री जी ने कहा, जाति-पाति का एक सिलसिला है जो ऊपर से चला आ रहा है और नीचे तक चला आया है। जब तक जाति-पाति के बन्धन नहीं टूटेंगे तब तक कोई बराबरी का दर्जा नहीं हो पायेगा। अस्पृश्यता केवल द्विजों और सो-काल्ड हरिजनों के बीच में ही नहीं है। अस्पृश्यता हरिजनों और हरिजनों के बीच में है, अस्पृश्यता ब्राह्मणों और ब्राह्मणों के बीच में है।

1924 में गांधी जी ने मेरे सुपुत्र यह काम किया कि मैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को हिन्दी सिखाने का काम करूं। मैं उनके गृह-नगर सेलम गया। वहां जाकर पहले दिन मैंने उनके लिए कुछ नोट्स बनाये। उनका बाहर का घर जरा दूर था, बीच में बड़ा लम्बा लान था, उसके बाद उनका भोजनालय था। भोजनालय में इतिफाक से, गलती से मैं अपने नोट्स छोड़ आया जो उनको साढ़े 3 बजे तीसरे पहर पढ़ाता था। जब मुझे याद आया तो मैं 2 बजे वहां गया। मेरी निगाह पड़ी, उनके

बड़े भाई भोजन पर बैठे थे, वे वेदपाठी ब्राह्मण थे। ऋग्वेद के दसों मण्डलों का पाठ करने के बाद वे एक बार भोजन करते थे। मैं वापस आ गया। जब राजाजी को पढ़ाने बैठा तो उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई को तुमने भूखा मार दिया। मैंने कहा 'बह कैसे'? उन्होंने कहा कि जब वे भोजन करने बैठे तो तुम वहां गये। मैंने कहा कि मैं गया था, मेरी नजर उन पर पड़ी। लेकिन मैं बहुत दूर था। उन्होंने कहा कि वे तो दृष्टि दोष मानते हैं। मैंने कहा कि मैं तो उत्तर भारत का एक बहुत ही पवित्र ऊँचे किस्म का ब्राह्मण हूँ और मैंने उतनी दूर से उनको देखा। उन्होंने कहा कि वे तो उत्तर भारत के ब्राह्मणों को बराबर का नहीं मानते, उनको तो दृष्टि-दोष लग गया।

1946 में काजिरखेल इलाके में नोग्राखाली में जबरदस्त हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ। हमें उसका पता नहीं था, बाबू पुरुषोत्तम दान जी टंडन ने कहा कि मालवीय जी बीमार हैं, चलो उनको देख आयें। सवेरे 5 बजे वे मुझे अपनी गाड़ी में बनारस ले गये। वहां जाकर हमने देखा कि मालवीय जी विश्वविद्यालय में अपने भवन में बैठे हुए थे बहुत उदासी से भरे हुए। गोपीनाथ कविराज, आचार्य क्षितिमोहन सेन, विश्वभारतीय के प्रिंसिपल, सब बहुत ही गमगीन, उदासी से भरे हुए बैठे थे। टंडन जी ने पूछा बाबू जी, क्या बात है। मालवीय जी ने कहा कि तुमने आज का अखबार नहीं देखा, नोग्राखाली में क्या हुआ काजिरखेल के इलाके में। पढ़ा उन्होंने, उन्हें दुःख हुआ। लेकिन आचार्य क्षितिमोहन सेन ने कहा, मालवीय जी महाराज, इसके पीछे एक बड़ी लम्बी ऐतिहासिक कहानी है और उन्होंने बताया कि वह कहानी यह है कि पूर्वी बंगाल में जो गांव हैं उनमें हालत यह है कि एक गांव में खाली कायस्थ रह रहे हैं, एक गांव में खाली ब्राह्मण मुखर्जी, बनर्जी रह रहे हैं, एक गांव में नमः शूद्र रह रहे हैं, एक गांव में खाली मुसलमान रह रहे हैं। कोई मुसलमान डाका गया, वहां से कुछ खा पी कर आया, उसे हैजा हो गया। उसके कपड़े वहाँ धोये गये तालाब में, पोखर में। नतीजा यह हुआ कि उस गांव भर के लोग हैजे से इतने आक्रान्त हुए—दूसरे गांवों से जो उनके रिश्तेदार आये थे, वे भी अपने साथ-साथ हैजा ले गये—कि मुसलमान गांवों में हजारों की तादाद में लोग मर गये। बचा कौन ? छोटे-छोटे बच्चे 6 महीने के,

9 महीने के, एक साल के, डेढ़ साल के बच्चे। आस-पास के हिन्दू गांव वालों ने सोचा कि इन बच्चों का क्या होगा। एक-एक हिन्दू परिवार ने एक-एक बच्चे को पाल लिया। नतीजा यह हुआ कि लगभग तीन हजार बच्चे आस-पास के हिन्दू गांवों के परिवारों ने पाल लिये, उनके लिए खेतीबाड़ी का इंतजाम किया। दो वर्ष, चार वर्ष, पांच वर्ष के बाद ढाका के एक मौलवी साहब आये। उन्होंने पूछा कि यहां हमारे मुरीद रहते थे, उनका क्या हुआ। मालूम हुआ कि उनके सब मुरीद सख्त हैजे में चल बसे। क्या कोई बच्चा है? लोगों ने बताया कि हां बच्चे बचे हैं। पूछा कहां हैं? कहा कि आस-पास के हिन्दू गांव हैं, उन में हैं। जब वे वहां गये और मौलवी साहब ने उन लोगों से पूछा कि आप के यहां वे बच्चे हैं तो उन्होंने कहा कि हां, और बच्चे को आवाज दी ओ अब्दुल रहमान, तोर पीर साहब एण्डेचेन। उन्होंने बच्चे को देखा, पूछा कि इस का घर, जायदाद वगैरह कहां है? बताया गया कि सब का इंतजाम है। सारा एकाउंट है। आप बच्चे को भी ले लीजिए और जायदाद भी ले लीजिए। हम ने इसकी सारी खेतीबारी सम्हाल रखी है। लेकिन उन्होंने कहां कि हम इन की खेतीबारी नहीं लेना चाहते। परिणाम यह हुआ कि ढाका लौट कर जब शुकवार के दिन उन्होंने जुमे की नमाज पढ़ी तो कहा कि मोप्राखली के हिन्दू इनसान नहीं हैं, फरिश्ते हैं और उन्होंने तमाम लोगों से कहा कि अल्लाह से दुआ मांगो कि वह इन हिन्दुओं की बढ़ती करे। उन का घर फूले-फले। यह खबर नदिया के ब्राह्मणों ने अम्बबारों में पड़ी। नवद्वीप के ब्राह्मणों ने इस के लिये एक पंडित सम्मेलन बुलाया और तीन दिन की बहस के बाद एक फैसला दिया। उन लोगों से पूछा गया कि उन बच्चों को छूने के बाद तुम्हारे घर की स्त्रियां रात्राघर यानी रसोई में, नहा कर जाती थीं, तो उन्होंने कहा कि 6 महीने के बच्चे को छूने के बाद बार-बार अगर पोखर पर नहाने जाना पड़े तो सारा दिन इसी में खतम हो जायगा। वह तो रात्राघर में, चौके में जाती थीं इसी तरह। इस बात को सुन कर पंडित सम्मेलन के लोगों ने फैसला दिया कि जिन हिन्दू परिवारों ने अपने घरों में उन बच्चों को पाला है उन को

जाति च्युत किया जाय। उन की लहकियों को और उनकी बहुओं को जो इस अवधि में समुराल से आयी हैं या मायके को गयी हैं उन परिवारों के लोगों को भी जाति च्युत किया जाय। वे सब परिवार जाति से बाहर कर दिये गए। परिणाम यह हुआ कि उन नवद्वीप के पंडितों ने तीन दिन के बाद यह व्यवस्था दी कि जिससे पचास हजार हिन्दू हिन्दू समाज से लात मार कर बाहर निकाल दिये गये।

इस छुआछूत, इस अस्पृश्यता ने न केवल हरिजनों को ही परेशान किया, बल्कि इसने पूरे हिन्दू समाज को जकड़ रखा है। जैसा कि हमारे भाई प्रकाशवीर जी ने कहा कि जब तक हमारे देश में जातिभेद रहेगा, तब तक इस का कोई इलाज नहीं निकल सकता। आज कैफियत यह है कि यह जाति भेद न केवल हिन्दुओं में है बल्कि यह मुसलमानों में भी है, यह सिखों में भी है और यह ईसाइयों में भी है। 1873 में पोप ग्रेगरी सेकेरल के नम्बूदरी ईसाइयों ने शिकायत की कि हम नहीं चाहते कि एड़वा ईसाई हमारे गिरजे में आये। तो उस के बाद, 1876 में पोप ग्रेगरी ने इस बात का ऐलान बुल, जारी किया कि कोई एड़वा ईसाई नम्बूदरी गिरजे में नहीं जायगा। तो आज हालत यह है कि इस जाति-पात ने हम लोगों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा है। लेकिन यह हमेशा से नहीं थी। आप देखें पराजर स्मृति, आप देखें याजवल्क स्मृति, आप देखें बोधायन स्मृति, कहीं भी इस का समर्थन आप को नहीं मिलेगा। कुरान में लिखा है कि सब इंसान बराबर हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। बाइबिल कहती है—सब इंसान बराबर हैं। न कोई बड़ा है न कोई छोटा। तब फिर यह बड़े और छोटे की भावना क्यों? फिर क्यों यह जाति-पात की, छुआछूत की और अस्पृश्यता की भावना फैली? इलाहाबाद में हमारे एक प्रोफेसर थे नईमुरहमान साहब। उन्होंने एक बहुत लम्बी फेहरिस्त रखी थी। मैंने एक दिन कहा कि यह क्या है। तो उन्होंने बताया कि हम लोग भटनागर कायस्थ हैं। फिर हम लोग मुसलमान हुए। तो जब हम अपने बच्चों की शादियां करना चाहते हैं तो इसी फेहरिस्त से ढूंढ कर शादी ब्याह करते हैं। भटनागर भटनागर में शादी होती है,

[श्री विश्वम्भर नाथ पांडे]

हम बाहर शादी नहीं करते। तो यह रोग न सिर्फ हिन्दुओं में है, न सिर्फ मुसलमानों में है, न सिर्फ ईसाईयों में है, बल्कि पूरे समाज के भीतर है। एक जमाना था कि जब बंगाल में जात-पात बहुत थी और उस समय कहा जाता था कि जात मारले तीन सेन—बिलसेन, केशवसेन, स्टेसेन अर्थात् बिलसन के होटल ने, केशव सेन के ब्रह्म समाज ने और रेल के स्टेशन ने सारी जात-पात को तबाह कर दिया। फिर ब्रह्म समाजी भी अपने जाति में दूँट कर जादी ब्याह करने लगे और हर जाति का उसी जाति में काम होने लगा। तो इस लिये आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात को सोचें और गंभीरता के साथ सोचें। यह रोग ऐसा है जिसने इस देश की जड़ें खोखली कर दी हैं। कब तक हम इस खोखलेपन को बर्दाश्त करेंगे? कब हम इसका एक परमानेंट इलाज निकालेंगे, जिससे कि पूरे समाज में चेतनता आये और यह समाज डेमोक्रेसी का सच्चे माने में उपभोग कर सके।

इसलिए मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इस बात को देखें कि यह कैसे किया जा सकता है और जैसा प्रकाशवीर शास्त्री जी ने सुझाव दिया है, एक व्यापक बिल इसके लिए लायें। जब तक इसका व्यापक रूप से इलाज नहीं निकालेंगे—घाप इलाज कर रहे हैं, छीक है—लेकिन उसके अंदर गहरे नहीं होंगे, गहरे नतीजे नहीं निकलेंगे गहरे नतीजे तब निकलेंगे जब हम कोई स्थाई इलाज करेंगे।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष जी, जो बिल हमारे सामने है, उसका मैं तहदिल से स्वागत करती हूँ। यों तो पहले भी ऐसे कानून बना रखे थे, लेकिन उनमें और मजबूती लाने के लिए आज जो कुछ चन्द लाइनें जोड़ी गई हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ। लेकिन इसके साथ ही मेरे दिमाग में यह शंका भी है कि क्या आज की जो जोड़ी हुई चन्द लाइनें हैं, वह समाज के अंश-अंश में व्याप्त इस जहर को हटा सकेंगी। यह जो छुआछूत का भेद है, यह हजारों वर्षों से इस मुल्क में चला आ रहा है। आजादी के 25—30 साल बाद हमने इसको मिटाने की कोशिश की, लेकिन बहुत कम दर्जे पर इसको कर पाये।

जब हम अपनी प्राचीन संस्कृति, इतिहास या धर्म को देखते हैं तो शायद हजारों वर्षों से कुछ

जातियाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर घोर अत्याचार होते रहे। उनको कभी इंसान की तरह से रहने का मौका नहीं दिया गया। बल्कि मैं कहूँगी कि एक साधारण से पशु कुत्ते के मुकाबले में हमारे समाज ने इन जातियों को जगह नहीं दी। हम देखते आये हैं, शास्त्रों में भी यह लिखा है कि अगर वेद का कोई शब्द किसी शूद्र के कान में पड़ जाय तो उसको शीशा गर्म करके उसके कान में डाल कर जला देना चाहिए। लिखा ही नहीं है, दक्षिण में ऐसे कांड हुए हैं। कहते हैं कि अस्पृश्य लोगों के कानों में गर्म-गर्म शीशा डाला गया और वे मारे गये। आज भी किसी ब्राह्मण के ऊपर छाया पड़ जाती है तो स्नान तो वह करता ही है, लेकिन उस अस्पृश्य को दण्ड दिया जाता है। इस तरह से एक घोर जुल्म और अत्याचार हम लाखों, करोड़ों, लोगों के साथ आज तक करते आये हैं। लेकिन गांवों में तो छुआछूत का चलन, प्रचलन अब भी चल रहा है, शहरों में कुछ कम है। हमारे देश के कुछ प्रान्तों में बहुत ज्यादा है, कुछ प्रान्तों में कम है। जब हम पंजाब की तरफ नजर डालते हैं तो उधर उतना नहीं है लेकिन दक्षिण की तरफ जाते हैं तो वहां पर छुआछूत आज भी उसी ढंग से चली आ रही है। तो इस छुआछूत को मिटाने के लिए केवल कुछ कानून को लाइनें इसमें बल नहीं दे सकेंगी। कुछ बल जरूर मिल सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति करने की जरूरत है। हमारे विचारों में बहुत जबरदस्त तब्दीली लाने की जरूरत पड़ेगी। कानून तो पहले भी बना हुआ है, लेकिन अगर हम देखें तो आज तक इन 20—25 वर्षों में इस कानून का इस्तेमाल कितने प्रतिशत लोगों के ऊपर हुआ है, तो पता चलेगा कि बहुत कम लोगों पर इसका इस्तेमाल हुआ है। अभी थोड़े दिनों की घटना बताती है। हमारी कंस्टीट्यूएंसों में एक अस्पृश्य जाति का लड़का था। वह पीछे बन गया था, उसको गांव के लोगों ने इस तरह से मारा पीटा, व उसको नहीं रखा गया। वह कलेक्टर के पास गया, लेकिन उसको कोई स्थान नहीं मिला। आखिर परेशान होकर उसका बाप उसको दिल्ली में लाया है और कहीं डेली वेजेज पर उसको रखा है। गांवों के स्कूलों में यह हालत है कि वे हरिजन बच्चों के हाथ का पानी भी नहीं पीते। एक नहीं अनेकों ऐसी बातें, ऐसे जुल्म हमारे समाज

में इन लोगों के ऊपर होते रहते हैं। हालांकि हमारे संविधान में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि कास्ट, ब्रीड एंड सेक्स के आधार के बिना सब को बराबर अधिकार दिए जाएं। पांडे जी ने भी कहा है कि सभी जीव बराबर हैं। कहने से, शास्त्र में लिखने से कुछ होने वाला नहीं है। संविधान में लिखना और बात है और व्यावहारिक दृष्टि से उसे लागू करना दूसरी बात है।

जो संबंधित मंत्री जी हैं उनके सामने मैं एक सुझाव रखना चाहती हूँ जो कानून से संबंधित है। जब सरकार यह कानून लाई है तब मैं यह कहना चाहती हूँ कि आज जो मंदिर है, मस्जिद हैं उनमें से कई मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश पर पाबंदी है। जो बड़े-बड़े मंदिर हैं, सरकार के ट्रस्ट बने हुए हैं उन ट्रस्ट वाले मंदिरों में भी हरिजनों का प्रवेश निषेध है। अभी कुछ महीनों पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि महाराष्ट्र के एक मंदिर में एक डिप्टी मिनिस्टर को जाने से रोक दिया गया क्योंकि वह ऊंची जाति का नहीं था। मैं अपने स्टेट का जिक्र करना चाहती हूँ। वहाँ नाथद्वारे का मंदिर है। यही नहीं वहाँ और भी बड़े-बड़े मंदिर हैं और करोड़ों रुपये सालाना उनकी आय है। वहाँ पर ट्रस्ट काम कर रहे हैं लेकिन उन मंदिरों में हरिजनों को जाने की इजाजत नहीं है। हरिजन वहाँ जा नहीं सकते हैं। मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब आप दूसरी चीजों पर कानून लगा रहे हैं तो जो आपके मंदिर हैं जिन पर आपके ट्रस्ट काम कर रहे हैं सबसे पहले उन मंदिरों को हरिजनों के लिये खोलिये। कागजी कानून से कुछ नहीं हो सकता। इसमें आपको आगे आना होगा। मैं सोचती हूँ कि अगर आप अपने मंदिरों में भी हरिजनों का प्रवेश डेके की चोट पर करा देंगे तो आपके कानून का कुछ हद तक मकसद पूरा हो जाएगा। वे बेचारे धर्म में, ठाकुर जी में, भगवान की मूर्ति में विश्वास रखने वाले हैं और उनके दर्शन करने के लिये तरसते रहते हैं। मैं जहाँ तक जानती हूँ समाज कल्याण विभाग से हरिजनों को अलग मन्दिर बनाने के लिये रुपया मिला है और उन्होंने अपने अलग ठाकुर जी कायम किये हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या भंगियों के ठाकुर जी अलग हैं और आपके ठाकुर जी अलग हैं? आप उनके लिये अलग मन्दिर बना कर, उनके अलग मन्दिर बनाने के लिये पैसा देकर छुआछूत को नहीं मिटा सकते। आप उनको अलग कुड़ियाँ बनाने के लिये पैसा देते

हैं तो क्या इससे छुआछूत मिट सकती है। जो सार्वजनिक कुएं हैं जहाँ से दूसरी जातियों के लोग पानी भरते हैं वहाँ पर हरिजनों को जाने का अधिकार क्यों नहीं देते हैं। आप उनके लिये अलग कुएं क्यों बनाते हैं?

मैं आपका ज्यादा वक्त न लेकर इतना निवेदन करना चाहूंगी कि जब तक समाज की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक ये जो छोटे-मोटे काम हैं पूरे नहीं किये जा सकते। इसलिए सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाय। हम देखते हैं कि जब कोई हरिजन लड़का अच्छी दुकान पर बैठा होता है और अच्छे साफ कपड़े पहने होता है तो सब लोग वहाँ पर कोकाकोला पीते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी गंदे कपड़े पहने होता है तो वहाँ पर कोई भी कोई चीज खाना पसंद नहीं करता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आर्थिक स्थिति का मनुष्य की जिन्दगी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम लोग इन लोगों को जो नौकरियों में इंसेंटिव दे रहे हैं वह तो देना ही चाहिए लेकिन हम सब लोगों को नौकरी नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ कि इन लोगों को हमें दूसरे धन्धों में भी इंसेंटिव देना चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि उनके लिए दूसरे रोजगारों का प्रबन्ध किया जाय। हम देखते हैं कि ड्राईक्लीनिंग के लिए स्तोबाइट जैसी बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ होती हैं जब कि सब काम धोबी करता है। ऐसी हालत में इस प्रकार के काम हरिजन लोगों को क्यों नहीं दिये जायें, इस पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप हरिजनों के लिए मंदिरों के द्वार खोलिये। सिर्फ कानून बनाने से ही काम नहीं चलेगा।

SHRI K. K. MADHAVAN (Kerala) : Sir, it was long ago that the Constitution of India abolished untouchability. But even before that, there was a movement for the annihilation of untouchability, right from the days when Dr. Ambedkar had to fight the social evil through his book, which was originally meant for a presidential speech at a meeting which did not take place. Later on it was published as a book. The meeting did not take place and he said many things in that which were very unpalatable to the would be

IShri K. K. Madhavan]

audience. This book is well known under the title "Annihilation of Caste". I for one say that abolition of untouchability alone cannot deliver the goods. We have to abolish the caste system also. Untouchability is a consequence of the caste system, and the caste system, in its turn, is a consequence of the "Chatur Varna" system. I do not want to deal with the theoretical aspect of this question. Whatever we have gained in India against untouchability is because of three factors: (1) By the resistance of the weaker sections of the society, the so-called untouchables; (2) by Governmental help; and (3) the most important of all, by the efforts of an enlightened section of the society in India. Of the three factors, the third factor for which Mahatma Gandhi is largely responsible, is gradually going down, now I do not know what the reason is. I have my own explanation, in the present context, in free India, the erstwhile untouchables have a sense of right, an awareness of their rights, and they have begun to assert. It is only natural that when the weaker sections of the people become aware of their rights and they begin to strike back or when they begin to assert themselves, certainly, the exploiters will have with redoubled vigour, a new programme for suppressing the underdog. That is exactly what happens. In many States, the cases of atrocities on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are on the increase. It is admitted even by the official quarters. Why does this happen? This happens simply because the casteist monopolists who look down upon these weaker sections of people as their slaves, cannot tolerate the later coming up. This is not untouchability, Sir. This is something worse than untouchability. This is an inhuman attitude which cannot be tolerated in any civilised society. This unsocial attitude is known under the nomenclature 'casteism'. Why does this casteism occur? This casteism occurs, I would say, because of untouchability, which has been declared, treated and punished as a crime. The basic law now being against it, it has

now gone underground, it has gone underground into the minds of men and there it reigns raising its ugly head in the form of a war of nerves the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I say, it is a perpetual war of nerves. This war of nerves cannot be defeated very easily. A war can be won only by a stronger force. In the case of a war of nerves also it can be won by a superior force combating the evil. That is what is happening in India. Some of our friends in this hon. House were saying that certain social service organisations like the Rama-krishna Mission, the Arya Samaj and some other Samajams, that they should take up the work, that the Scheduled Caste leaders should themselves take up the work. We are prepared, Sir. We are actually doing that work. Nobody need advise us on that account. But I would ask, is it enough for hon. Members to sit in their armchairs and exhort people to do the job for them? I would say, Sir, that it is the duty of these people, the leaders of this country, to take up the cause and fight it to extinction as the Father of Nation has done.

Now, Sir, though I admit that this is a progressive Bill and it provides for so many good things, still I have a feeling that there is a section which ought not to have found a place in this Bill. What is that section? That is clause 2 of section 17 of the Bill which seeks to amend section 15 of the principal Act. Now, clause (2) of section 17 of the Bill says: "Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, when any public servant is alleged to have committed the offence of abetment of an offence punishable under this Act, while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, no court shall take cognisance of such offence of abetment except with the previous sanction (a) of the Central Government in the case of a person employed in connection with the affairs of the Union, and (b) of the State Government, in the case of a person employed in connection with the affairs of a State." Sir, why this exemption? Sir, this protection aggravates the

caste mentality of the officers. My complaint is : "why do you provide this section" ? I am getting hundreds of complaints against casteism being practised in Government offices in the matter of appointments as well as administration at air stages in public sector undertakings are much worse.

SHRI N. H. KUMBHARE : This amendment is made at the instance of the Government. This is a Government amendment, otherwise there was no such provision.

SHRI K. K. MADHAVAN : Casteism largely is the cause of our disability whereas untouchability is under control. The disease has assumed the new form of casteism in Government offices and in farms and factories. In the farms where the workers refuse to be dictated by others, we find that by the substitution of the new provision in section 15 Government servants will be protected and only the Government will have the power to sanction prosecution against them. Sir, it is the right of a private citizen to complain if he is discriminated against. Why should the aggrieved Scheduled Caste citizen be denied of that right to take the matter to a court of law. If the wrong-doer is an officer of the Central Government it is only the Central Government which has the powers to take legal proceedings against him. If he happens to be a public servant of a State Government it is only the State Government which is competent to institute proceedings against him. Why should these public servants be given this exemption, this protection ?

[The Vice-Chairman (Shri Ranbir Singh) in the Chair]

It is unwarranted, Sir. I should say that clause (2) of section 17 of the bill should be taken away from the Bill for the simple reason that it places the victim of the wrong at a disadvantage when he files a complaint. This clause (2) of section 17 of the Bill is a black spot on this legislation. It is not consistent with the spirit of our democracy; it is not 28 RSS/76-4

consistent with the spirit of the 20-point programme which has been hailed from all quarters. So, I would suggest that better wisdom should prevail against this clause.

Sir, I was referring to casteism entertained in Government offices and at other public places. Such public places are not mentioned in this Bill or in the principal Act. That is the deficiency. This deficiency has to be made good. How should it be made good? I would suggest that the amplitude of this Act should be made wider so as to include anti-Harijan, anti-tribal, attitude and discriminatory actions of Government officers punishable within the Act. Unless that is done, the administration would not improve, would not become free from casteism.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : Try to wind up now.

SHRI K. K. MADHAVAN : Sir, unless this is done our social system and our democracy will not progress. Thank you, Sir.

SHRI ABU ABRAHAM (Nominated) : Mr. Vice-Chairman, Sir, every year, a few times we, in Parliament discuss the subject of untouchability of Harijans and we have done this for many years now. But since independence, it seems that the condition of Harijans has not changed very much. We still read in the newspapers everyday of open discrimination against Harijans, violence against them, their living conditions also remaining the same. We have cases of landlords attacking Hari-jan villages and the police doing nothing about it. The Harijans get arrested very often and the landlords get away with it. We have to consider why the situation is like this. Why, after so many years and after trying to do so much, have we made so little progress? I think it is because we have an attitude of doing charity to the Harijans like the salvation army used to do the poor in the old days. And this has got to change. What we have to do is to improve the political and economic power of the Harijans. Unless we do

tShri Abu Abraham! that, it will be very hard for any legislation to improve their condition.

Sir, this Bill is a progressive Bill, a radical Bill and its provisions, I am sure, will give to untouchables the legal right that they deserve and should have. But this is not enough. I think we have to attempt to make radical changes in the social structure, the basic structure of our society. Unless that is done, we cannot expect the conditions of the Hari-jans to improve very much.

The important point to be considered here is that Harijans themselves should have the means to defend themselves and to look after their interests. They will have to organise themselves. They will have to educate themselves. They will have to take a greater part in the democratic processes in this country. It is these things that matter and the Government should try to help them, enable them to assert themselves and to organise themselves. But so long as the Harijans remain largely illiterate, they will neither be able to defend themselves nor make any economic progress. I know that the recent measures of land distribution to the landless has helped Harijan communities in many parts of the country but a great deal more needs to be done. There has to be a massive attempt to educate the Harijans, to give them literacy, to give them the basic tools with which they can improve their conditions. Sir, for example, Kerala's work in this matter is worth-noting. A hundred years ago, when Swami Vivekananda visited Kerala, he said that this was the most reactionary State that he had ever been to. In those days, there was not only untouchability, but there was also unapproachability and unseeability. Today, if you go to Kerala, you can see the difference. This is not necessarily because of legislation, not even by propaganda or by charitable acts, but by organising the rural labour and the industrial labour and by giving them the tools and the means by which they could fight for their rights. This is what should have been done in other States also. This has been done in Kerala.

neraia has a very high level of education and this has made a tremendous impact in destroying the caste system. I do not say that it is completely destroyed. But it is very negligible now. Privately, people may have prejudices. But in most parts of Kerala, it is very difficult to see any open discrimination against the harijans. The Kerala Government have built houses for the poor people. In these houses, the harijans live side by side with the other people who belong to the higher castes. It is not so in other States. In the other States, separate housing schemes are there for the harijans.

SHRI K. K. MADHAVAN : For the information of the hon. Member, I would like to state that in Kerala the harijan population is not segregated generally.

SHRI ABU ABRAHAM : This is what I am saying. But in the old days, there were segregated areas where the harijans lived. Therefore, our most important task should be the desegregation of the harijan population. When we build hostels for students, they should be for every one. Why should there be harijan hostels? If such is the case, why not we have buses and trains exclusively for the harijans? It has been said that the Railways have made a great contribution in changing the social pattern in this country because in our trains the harijans and other people travel together. In the same way, I think we should have common hostels, we should have hostels where the harijan boys can stay along with the boys belonging to the higher castes. In any case, it has been proved to be a racket where these people have been exploited and people have been making money. This is a well known fact.

Sir, we say all the time that we are a secular State and we are getting more and more secular as years pass by. But the interesting thing is that while we say that we are becoming more secular, it seems to me that we are getting more and more religious. I do not see any attempt being made in this country to break the hold of religious orthodoxy on our society. Now,

many distinguished people, political leaders, and high dignitaries seen to be encouraging orthodox. In this connection, I would like to give the example of the revival of the cow protection campaign. May I ask why the ban on cow slaughter has so suddenly been introduced in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Maharashtra? This has directly affected poor people in this country. This has directly affected the harijans in this country. I can only say this is a way of encouraging religious orthodoxy. The other day Shri Vinoba Bhave made an extraordinary remark that vegetarianism is the answer to the removal of untouchability. Now this is a direct insult to all people who eat meat. The implication of that remark is that people who eat meat automatically go down the social ladder. On the contrary, I say that people must all be encouraged to eat meat so that they can all achieve equality. This should be the aim of the Government and they should not give in to Vinoba Bhave. Any agricultural scientist will say that we have too many cattle in this country and it is necessary to have a certain amount of slaughter and meat-eating.

Sir, the new duties of citizens include "the cultivation of a scientific temper" and is it too much to ask the Government itself to show a scientific temper in this matter?

شری سکندر علی وجہ (مہاراشٹر) :

جناب وائس چیرمین صاحب - میں اس بل کی تائید کرتا ہوں - اس میں جو سزائیں مقرر ہیں یا جو پابندیاں ہریجنوں کے مخالفوں کے لئے موجود ہیں وہ بہت وقتی ہیں اور ان کی بہت ضرورت تھی۔ ایک بات مجھے اور کہنی ہے خاص طور پر - ابھی میں مراٹھہ واڑہ کا دورہ کر کے آ رہا ہوں اور میں وہاں گاؤں گاؤں گیا - میں نے کچھ زیادہ تبدیلی وہاں دیکھی نہیں۔ میں ہر بستی میں گیا - مانگواڑوں میں دھیڑ واڑوں میں اور دوسری جگہوں پر بھی۔ ان کے الگ کنوین ہیں وہاں وہ رہتے

ہیں اور ان کی جو چائیس برس پہلے حالت تھی آج کچھ زیادہ فرق اس میں نہیں آیا ہے۔ میں بھی ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں جہاں کا میں پائل ہوں اس لئے میں جانتا ہوں کہ حالت کیا ہے۔ میں نے وہاں پوچھا کہ آخر بات کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جن لوگوں کے پاس ہریجن سدھار کا یعنی شیڈولڈ کسٹ کے سدھار کا کام ہے وہ سرکاری نوکری تو کرتے ہیں لیکن اس کام میں ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے اس پر ان کو بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن ایسے کچھ مخلص لوگ ہیں جو کہ واقعی اس میں عقیدہ رکھتے ہیں اس کام کو ایسے لوگوں کے سپرد کرنا چاہئے اگر ہم ان کی حالت میں کوئی سدھار لانا چاہتے ہیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہریجن بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے کالج الگ ہونے چاہئیں ہمارے ہوسٹل الگ ہونے چاہئیں - ایک اور بات میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہمارے لائق دوست اب تو ہریجن لفظ کو بھی پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیڈولڈ کسٹ کہو - گاندھی جی نے یہ کیا نیا لفظ گھڑ لیا تھا - میں اس بات کا قائل ہوں کہ ڈاکٹر امبیڈکر بڑے عالم فاضل تھے - انہوں نے ہریجنوں کی بڑی خدمت کی لیکن گاندھی جی نے بھی کم خدمت نہیں کی شیڈولڈ کسٹ کی انہوں نے ان کو بہت اعلیٰ سطح پر لاکر کھڑا کر دیا - مجھے معلوم نہیں کہ کتنے لوگوں کے یہاں کھانا بنانے والے ہریجن ہیں - میں سیواگرام گیا وہاں میں نے دیکھا کہ کھانا پکانے والی لڑکیاں ہریجن ہیں - کھانا پروسنے

[شری سکندر علی وحید]
والے دینے والے ہریجن ہیں۔ یہ ہے
پریکٹیکل ہریجن سدھار۔ معلوم نہیں
ہمارے کتنے منسٹروں کے یہاں ہریجن
نوکر ہیں یا دوسری ذلت کے لوگ
ہیں ہمارا سیکولرزم تو ہماری
چمڑی کے بہت نیچے نہیں گیا ہے۔
ہریجنوں کی بات تو دور رہی۔ ابھی
اس ہاؤس میں بات چل رہی تھی کہ
شادیاں ہونی چاہئیں انٹر کاسٹ۔ اس
سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔
مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی لیکن میں
آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دہلی بڑا ترقی
یافتہ شہر ہے بڑا کاسٹ موپولیشن شہر
ہے یہاں اورنگ آباد کی ایک مسلمان
لڑکی نے ایک ہندو سے شادی کر لی۔
کہنے کو اس کا شوہر بڑا آفیسر ہے
لیکن چودہ سال ہو گئے اور اسے
بارہ مکان بدلنے پڑے ہیں۔ ہر جگہ
یہ کہا گیا کہ یہ تو مسلمان ہے اس
نے کہا کہ میں تو ہندو ہوں تو
جواب ملا کہ تمہارا باپ تو مسلمان تھا
اسی لئے ان کو مکان نہیں ملتا۔ ہمارے
اوم مہتہ جی اس وقت منسٹر تھے میں
نے کہا کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ ہم
کانگریس کے لوگ کیسے کہیں کہ
لوگوں کے سامنے کہ بھائی سب کے لئے
برابر حق ہے۔ آپ ان کو مکان کیوں
نہیں دیتے ہیں۔ مدراس میں تو انعام
ملتا ہے۔ انہوں نے کہا بات تو ایسی
ہی ہے اس کے بعد میں نے بھولا پاسوان
شاستری سے کہا کہ آپ تو شیڈولڈ
کاسٹ کے آدمی ہیں۔ میں چاہتا ہوں
کہ یہ شادی جو ہوئی ہے اس پر ان کو
مکان ملنا چاہئے ورنہ میں ان کو
اندرا جی کے پاس لے جاؤں گا اور کہوں
گا یہ لیڈر جھوٹ بولتے ہیں۔

جب کوئی لیڈر کہتا ہے کہ سیکولرزم
آگیا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ
جھوٹ بول رہا ہے۔ جب بھولا پاسوان
شاستری جی نے ان کا نام ۲۵ نمبر اوپر
کر دیا تب ان کو مکان ملا۔ میں
یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایسے
بھی لوگ ہیں۔ یہ لوگ جو سیکولرزم
کا پرچار کرتے ہیں یہ کچھ نہیں
ہے۔ اس کے معنی لوگوں کو کم
سمجھ میں آئے ہیں۔ اگر میں دیکھوں
گا کسی برہمن کے گھر میں ہریجن کھانا
پکانے والا ہو کسی سید سادات کے گھر
میں ہریجن کھانا پکانے والا ہو تو ہم
کہیں گے کہ سیکولرزم یہ ہے۔ میرے
پاس ایک درخواست آئی ہے۔ ہم کہتے
ہیں کہ ہریجنوں کو کچھ مل گیا
مسلمانوں کو کچھ مل گیا۔ میں
پوچھنا نہیں چاہتا کہ کتنے مسلمان
پولیس میں ہیں کتنے کس ڈپارٹمنٹ میں
ہیں ہمارے چیف منسٹر کے وطن پٹھن
میں ایک جلسہ ہوا وہاں کچھ لوگ
آئے وہ بھنگے سماج کے لوگ ہیں خانہ
بدوش لوگ آبادی کے لحاظ سے صرف
مہاراشٹر میں ۱۵ سے ۲۰ لاکھ وہ لوگ
ہیں۔ ہزاروں سال گذر گئے آج تک ان
کو کوئی مکان کوئی زمین نہیں ملی۔
آپ تو زمین کی بات کرتے ہیں ہم نے ان
سے پوچھا کیا تم کو مکان کبھی نہیں
ملا۔ انہوں نے جواب دیا ہمیں زمین سے
کیا تعلق جہاں گاؤں میں کام ملتا ہے
وہاں ہم رہتے ہیں اور کام ختم ہو جاتا
ہے تو دوسرے گاؤں میں چلے جاتے ہیں۔
ہمارے شیڈولڈ کاسٹ اور دوسرے بھائیوں
کو بہت حقوق ملے ہیں لیکن انہوں نے
کہا کہ ہزاروں برسوں سے ہم کو کوئی
مکان نصیب نہیں ہوا۔ جب ان کا لیڈر
گھونسلے بولنے کے لئے کھڑا ہوا تو

میں نے گاؤں گاؤں دیکھا ہے جب سے میں فریہ دیکھا ہے کہ ۲۰ لاکھ

†[श्री सिकन्दर अली वज्र (महाराष्ट्र) : जनाब वाइस चेयरमैन माहब, मैं इस बिल की तारीफ करता हूँ। इस में जो मजार्जे मुकरर हैं या जो पाबन्दिया हरिजनों के मुखालिफों के लिये मौजूद हैं वह बहुत बस्ती हैं और उन की बहुत जरूरत थी। एक बात मुझे और कहनी है खास तौर पर। अमी मैं मराठ-वाड़ा का दौरा कर के आ रहा हूँ और मैं वहाँ गांव-गांव गया। मैंने कुछ ज्यादा तदीनी वहाँ देखी नहीं। मैं हर बस्ती में गया, मागवाड़ा घेड़ वाड़ी में और दूसरी जगहों पर भी। उन के अलग कुएं हैं। वहाँ वह रहते हैं और उन की जो चालीस बरस पहले हालत थी आज कुछ ज्यादा फर्क उन में नहीं आया है। मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ, जहाँ का मैं पाटिल हूँ। इसलिये मैं जानता हूँ कि

†[] Hindi Translation.

[श्री सिकन्दर अली वज्र]

हालत क्या है। मैंने वहाँ पूछा कि आखिर बात क्या है। तो पता चला कि जिन लोगों के पास हरिजन मुधार का यानी शेड्यूल्ड कास्ट के मुधार का काम है वह सरकारी नौकरी तो करते हैं, लेकिन उस काम में उन का कोई अकीदा नहीं है। उस पर उन को भरोसा नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ मुखलिस लोग हैं कि जो वाकई इसमें अकीदा रखते हैं। इस काम को ऐसे ही लोगों के मुपुर्द करना चाहिए अगर हम उन की हालत में कोई मुधार लाना चाहते हैं तो। बदकिस्मती तो यह है कि हमारे हरिजन भाई कहते हैं कि हमारे कालेज अलग होने चाहिए, हमारे होस्टल अलग होने चाहिए। एक और बात मैं कभी कभी सोचता हूँ। हमारे लायक हरिजन दोस्त अब तो हरिजन लपज को भी पसंद नहीं करते। वह कहते हैं कि हमें शेड्यूल्ड कास्ट कहो। गांधी जी ने यह क्या नया लपज घड़ लिया था। मैं इस बात का कायल हूँ कि डा० अम्बेदकर बड़े आलमि फाजिल थे। उन्होंने हरिजनों की बहुत खिदमत की। लेकिन गांधी जी ने भी कम खिदमत नहीं की शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की। उन्होंने उन को बहुत आला सतह पर ला कर खड़ा कर दिया। मुझे मालूम नहीं कि कितने लोगों के यहां खाना बनाने वाले हरिजन हैं। मैं सेवाग्राम गया और वहां मैंने देखा कि खाना पकाने वाली लड़कियां हरिजन हैं, खाना परोसने वाले, देने वाले भी हरिजन। यह है प्रेक्टिकल हरिजन मुधार। मालूम नहीं हमारे कितने मिनिस्ट्रों के यहां हरिजन नौकर हैं या दूसरी जाति के लोग हैं, हमारा सेकुलरिज्म तो हमारी चमड़ी के बहुत नीचे नहीं गया है, हरिजनों की बात तो दूर रही। अभी इस हाउस में बात चल रही थी कि शादियां होनी चाहिए इंटरकास्ट। इस से बड़े मसले हल हो जायेंगे। मुझे यह सुन कर खुशी हुई, लेकिन मैं आप को बताता हूँ कि यह दिल्ली बड़ा तरकीयाफत शहर है, बड़ा कास्मोपोलिटन शहर है। यहां औरंगाबाद की एक मुसलमान लड़की ने एक हिन्दू से शादी कर ली। कहने को उसका शौहर बड़ा अफसर है लेकिन 14 साल हो गये और उसे 12 मकान बदलने पड़े हैं। हर जगह यह कहा गया कि यह तो मुसलमान है। उस ने कहा कि मैं तो हिन्दू हूँ तो जवाब मिला कि तुम्हारा बाप तो मुसलमान था। इस लिये उन को मकान नहीं

मिलता था हिन्दू वस्तियों में। हमारे श्रीम् मेहता जी उस वक्त मिनिस्टर थे। मैं ने कहा कि यह क्या होता है। हम कांग्रेस के लोग कैसे कहें लोगों के सामने कि भाई सबके लिए बराबर हक है। आप इनको मकान क्यों नहीं देते हैं। मद्रास में तो इनाम मिलता है। उन्होंने कहा बात तो ऐसी ही है। इसके बाद मैंने भोला पासवान शास्त्री से कहा कि आप तो शेड्यूल्ड कास्ट्स के आदमी हैं, मैं चाहता हूँ कि यह शादी जो हुई है इस पर इनको मकान मिलना चाहिए। वरना मैं इनकी इंदिरा जी के पास ले जाऊंगा और कहूंगा कि यह लीडर झूठ बोलते हैं। जब कोई लीडर कहता है कि सेक्यूलरिज्म था गया है तो मैं कहना चाहता हूँ कि वह झूठ बोल रहा है। जब भोला पासवान शास्त्री जी ने उनका नाम 25 नम्बर ऊपर कर दिया तब उनको मकान मिला। मैं यह भी कहता हूँ कि हमारे यहां ऐसे भी लोग हैं। यह लोग जो सेक्यूलरिज्म का प्रचार करते हैं यह कुछ नहीं है। इसके माने लोगों को कम समझ में आते हैं। अगर मैं देखूंगा किसी ब्राह्मण के घर में हरिजन खाना पकाने वाला हो, किसी सैयद सादात के घर में हरिजन खाना पकाने वाला हो तो हम कहेंगे कि सेक्यूलरिज्म यह है। मेरे पास एक दरख्वास्त आई है। हम कहते हैं कि हरिजनों को कुछ मिल गया, मुसलमानों को कुछ मिल गया। मैं पूछना नहीं चाहता कि कितने मुसलमान पुलिस में हैं, कितने किस डिपार्टमेंट में हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर के वतन पैटन में एक जलसा हुआ। वहां कुछ लोग आये। वह भटके समाज के लोग, खाना-बदोश लोग आवादी के लिहाज से सिर्फ महाराष्ट्र में 15 से 20 लाख के लोग हैं। हजारों साल गुजर गये, आज तक उनको कोई मकान, कोई जमीन नहीं मिली। आप तो जमीन की बात करते हैं, हमने उनसे पूछा क्या तुमको मकान कभी नहीं मिला? उन्होंने जवाब दिया हमें जमीन से क्या ताल्लुक। जहां गांव में काम मिलता है वहां हम रहते हैं और काम खत्म हो जाता है तो दूसरे गांव में चले जाते हैं। हमारे शेड्यूल्ड कास्ट और दूसरे भाइयों को बहुत हुकूम मिले हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हजारों बरसों से हमको कोई मकान नसीब नहीं हुआ। जब उनका लीडर भौसले बोलने के लिए खड़ा हुआ तो हमारे मिनिस्टर साहब भी उसकी तरदीद नहीं कर सके, क्योंकि सच्ची बात की कोई तरदीद नहीं कर सकता, कि उनको कोई मकान नहीं मिले हमारे मुल्क में।

करोड़ों की आबादी है खानाबदोशों की, उनका कोई हिसाब है ? उनका कहीं नाम नहीं है शौडूल में, मगर वह मौजूद है, उनका बज्रूद है । 15 लाख आदमी महाराष्ट्र में फिर रहे हैं, गांव-गांव में, उनका कोई घर नहीं, कोई खेत नहीं, कोई मकान नहीं है । हमने हरिजन और शौडूल कास्ट के लोगों को मकान दिलाये, घर दिलाये, गाँवें दिलाई, बकरियां दिलाई, शोपड़ी दिलाई, यह अपनी जगह पर है । लेकिन 15 लाख खानाबदोशों को मकान नहीं हैं, जमीन नहीं है उनकी जिन्दगी ऐसी है । बदकिस्मती देखिये, उनके भी कई कबीले हैं, कई जातें हैं । मैंने उनसे पूछा कि आपके यहां आपस में शादियां होती हैं तो उन्होंने कहा शादियां नहीं होती हैं । यह जाति-भेद वहां तक भी पहुंचा है । तो यह मसला बहुत ही पेचीदा है । यह शौडूल कास्ट के मसले से भी बढ़कर बात है । अब तो गोया मैं खानाबदोशों का लीडर हूं ।

उप-सभाध्यक्ष (श्री रणवीर सिंह) : 20 नुकता प्रोग्राम में उनको मकान दिलाइये अपने राज्य में ।

श्री सिकन्दर अली वज्द : जिनके घर नहीं हैं, जिनकी इज्जत नहीं है, मैं उनका लीडर हूं । उनकी यह जो दरखवास्त आई है यह फैन्ट्स और फिगर्स के साथ है । मैं उम्मीद करता हूं कि यह हाउस इस मामले में मेरा साथ देगा ।

मैंने गांव-गांव देखा है । जब से मैंने यह देखा है कि 20 लाख आदमियों के पास घर नहीं है, खेत नहीं है, शोपड़ी नहीं है, कोई सहारा नहीं है तब से मेरा दिल बैठ गया । मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि सरकार शौडूल कास्ट्स के लिये बिल लाई है पर मैंने देखा है इन खानाबदोशों की मदद करने के लिये कानून में कहीं जिक्र नहीं है, कंस्टीट्यूशन में भी नहीं है, आपके इस बिल में भी कहीं नहीं है ।

उप-सभाध्यक्ष (श्री रणवीर सिंह) : यह सब 20 नुकते प्रोग्राम में है ।

श्री सिकन्दर अली वज्द : आप भी ऐसे इलाके से आते हैं जहां गांव के लोग रहते हैं । आप में भी ताकत है, जोश है, लोगों की खिदमत करने का जज्बा है । खुद हमारे ओम् मेहता जी हैं, उनसे और सभी दोस्तों से अपील करूंगा कि इन लोगों के लिये जिनके पास कुछ नहीं है, जिन्दगी में कोई सहारा नहीं है, रहने के लिये मकान नहीं है, उनकी मदद करें । शुक्रिया ।]

श्री कल्प नाथ राय (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, सरकार के द्वारा अस्पृश्यता निवारण का जो कानून आया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । केवल कानून से किसी समस्या का निराकरण नहीं होता । पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि दहेज प्रथा खत्म होगी, दहेज लेने वाले दंडित होंगे लेकिन दहेज प्रथा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है । पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि बाल विवाह खत्म होगा लेकिन फिर भी करोड़ों की संख्या में बाल विवाह हो रहे हैं । जब कोई चीज जनता के दिलों में बस जाती है तो पार्लियामेंट उस पर मोहर लगा देती है, सही मानों में वह उसका एक अमली रूप होता है । मैं इस सदन के माध्यम से सर्वप्रथम देश की 60 करोड़ जनता की तरफ से इस देश की महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी का अभिवादन करना चाहता हूं जिन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रमों के माध्यम से कर्ज की समाप्ति, हरिजन-गिरिजन में जमीन का बंटवारा एवं हरिजनों को सामाजिक जीवन में प्राथमिकता देने का एक शंखनाद फूँका है । हमारे देश की नेता प्रधान मंत्री ऐसी खुशकिस्मत हैं कि जिन्होंने छुआछूत के बंधन को खुद तोड़ा और अपने परिवार से तोड़ाया और ऐसा करने के लिये 60 करोड़ जनता का आवाहन किया ।

उपसभाध्यक्ष जी, जब तक इस देश में सीता और शम्भूक का अपमान होता रहा तब तक हिन्दुस्तान विदेशी हमलावरों के सामने पराजित होता रहा । जब इस मुल्क का नेतृत्व सीता के हाथ आया और इसकी रक्षा का भार शम्भूक के हाथ आया तब इस मुल्क के सेनानियों ने विदेशी हमलावरों को जबरदस्त पराजय दी ।

उपसभाध्यक्ष जी, अस्पृश्यता जातिवाद के पेट से पैदा हुई । इसलिए गुनार जार्ज ने लिखा है :

"The countries of the world are either vertically divided or horizontally divided but India is the only country which is vertically as well as horizontally divided."

दुनिया के सभी राष्ट्रों में या तो आर्थिक समस्या है या सामाजिक समस्या है । हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां सामाजिक उत्पीड़न है, आर्थिक उत्पीड़न है । पूँजीवाद के पेट से आर्थिक उत्पीड़न

[श्री सिकन्दर अली बख्त]

पैदा हुई और ब्राह्मणवाद के पैतृ से और जातिवाद के पैतृ से अस्पृश्यता पैदा हुई। जातिवाद के कारण ही हिन्दुस्तान के लोग हजारों वर्षों तक गुलाम रहे। इस जातिवाद और ब्राह्मणवाद ने देश की जनता के मन को तोड़ा है और पूंजीवाद ने देश की जनता के धन को तोड़ा है। ब्राह्मणवाद और जातिवाद ने इस देश के करोड़ों इंसानों के मन को तोड़ा है। अंग्रेजी भाषा के प्रचार से इन देश के करोड़ों लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहना पड़ा। जब तक देश में जातिप्रथा को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक इस देश का उत्थान नहीं हो सकता है। इस जाति प्रथा को तोड़ने के लिए कबीर से लेकर गुरु नानक, स्वामी दयानन्द सरस्वती और महात्मा गांधी ने अपने जीवन भर प्रयास किया और उसी परम्परा के अनुसार पंडित जवाहर लाल नेहरू ने और अब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने प्रयास किया है। जब तक इस देश से जातिवाद का अंत नहीं होगा तब तक हम ऊपर नहीं उठ सकते हैं। इस देश की दौलत आज किन लोगों के हाथों में है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इस देश की दौलत का हिस्सेदार अनटर्चबल नहीं माना जाता है। यद्यपि उनको नौकरियों में स्थान दिया गया है लेकिन नौकरियों में उनका हिस्सा बहुत थोड़ा है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिन्दुस्तान के हरिजनों को देश की दौलत में हिस्सेदार बनाना होगा, जमीन में हिस्सेदार बनाना होगा। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि जातिवाद पर चतुर्दिक रूप से हमला किया जाय। जब तक जातिवाद नहीं टूटेगा तब तक इस देश से अस्पृश्यता का निवारण नहीं हो सकता है। इस मुल्क के अन्दर कई वर्षों से हरिजन ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहा है। आज हमारे देश में वणिष्टी ब्राह्मणवाद कट्टरतापूर्वक हमारी संस्कृति के ऊपर बैठ गया है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि इस जातिवाद को समूल नष्ट किया जाय। पूजहूँ बिप्र सकल गूणग्राही इस प्रकार की जो बातें हैं उनको बदलना होगा, साहित्य को बदलना होगा। आप जानते हैं कि इस जातिवाद के कारण ही इस मुल्क में करोड़ों लोगों को मुसलमान होना पड़ा और जातिवाद के कारण ही करोड़ों लोगों को ईसाई होना पड़ा। *Water always percolates from above.* पानी ऊपर से आता है। ब्राह्मणवाद के कारण ही

इस देश में हरिजनों पर अत्याचार हुए। एक हरिजन गांव के कुएं पर पानी नहीं पी सकता है। यही नहीं हरिजनों में बहुत-सी उप-जातियां हैं। जहां तक मैं जानता हूँ, हरिजनों में 47 जातियां हैं। ऐसी हालत में आज जरूरत इस बात की है कि जाति प्रथा पर चतुर्दिक रूप से हमला किया जाय। मुझे इस बात की खुशी है कि इस देश की महान् नेता श्रीमती इंदिरा गांधी न केवल इस मुल्क से जाति प्रथा को समूल नष्ट करने के लिए कृत-संकल्प हैं बल्कि वे एशिया और अफ्रीका से उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और रंगभेद को भी समाप्त करने का प्रयास कर रही हैं। अल्जीर में जो तान-एलाइन्ड कट्टीज की कांग्रेस हुई थी उसमें उन्होंने यह मांग की थी कि दुनिया से रंगभेद की नीति समाप्त होनी चाहिए। हिन्दुस्तान के अन्दर भी उन्होंने जातिप्रथा को तोड़ने का एलान किया है। मैं समझता हूँ कि जब तक हम इस देश से जातिप्रथा को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम दुनिया से रंगभेद की नीति को समाप्त नहीं कर सकते हैं। इस देश की महान् नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी इस देश के 60 करोड़ लोगों को आवाहन किया है कि इस देश से जातिप्रथा का अन्त किया जाय। इस जाति प्रथा ने हमें सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा। इसलिए जब तक हम इस जाति प्रथा को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बन सकते हैं।

आदरणीय उप-सभाध्यक्ष महोदय, आज हिन्दुस्तान के अन्दर सात लाख गांवों में हरिजनों के लिए अलग चमराट बने हुए हैं। जब तक इन गांवों के अन्दर चमराटों को समाप्त करके हरिजनों को गांव वालों के साथ नहीं बसाया जाएगा तब तक इस देश से जाति प्रथा का अन्त नहीं हो सकता है। आज हम स्वयं हरिजनों के लिए हरिजन कालोनियां और हरिजन छावनों के लिए हरिजन छात्रावास बनाते हैं। जब तक आप इस भेदभाव को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हमारे देश से छुआछूत समाप्त नहीं हो सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए हमें हरिजनों को नौकरियों में हिस्सेदार बनाना होगा, व्यापार में हिस्सेदार बनाना होगा और जमीन के अन्दर हिस्सेदार बनाना होगा।

अब मुझे आपसे अन्तिम बात निवेदन करनी है और मैं आपका ध्यान दुनिया के रंग मंच की ओर ले जाना चाहता हूँ।

आप गांव की स्थिति का अध्ययन कीजिये। आज गांव की क्या हालत है? एक गांव के अन्दर ब्राह्मण है। ब्राह्मण अगर गांव के बीच में है तो उसके अगल-बगल अहीर, कुरमी, काछी, चमार बसते हैं। हर गांव के दक्षिण में एक चमरावट बनती है। आज दुनिया की बिरादरी में यूरोप, अमरीका और जो उधर के रहने वाले लोग हैं वे दुनिया के ब्राह्मण हैं, जो 28 हजार प्रति व्यक्ति आमदनी रखते हैं—अरब मुल्क—वे दुनिया के ब्राह्मण हैं और दुनिया के कुवैत, चीन, जापान, आज अहीर कुरमी और काछी हैं और हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और अफ्रीका की वही स्थिति है जो गांव के दक्षिण में बसने वाले हरिजनों की है, उधार बस्त्र, उधार कारखाने और उधार धन पर अपना जीवन चला रहे हैं। ये विकसित यह चाहते हैं कि हम दुनिया के ब्राह्मण बने रहे। तो हमें हिन्दुस्तान में जाति प्रथा को खत्म करना होगा और समूचे देश को श्रीमती इन्दिरा गांधी के सपनों का हिन्दुस्तान बनाना होगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।

डा० चन्द्रमणि लाल चौधरी (बिहार) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, इस पर काफी बहस सुबाहिसा हो चुका है। मैं इस बिल की तहे दिल से तारीफ करता हूँ और डिप्टी मिनिस्टर साहब और ओम मेहता जी को सुबारकवाद देता हूँ। यह उनके ही विभाग की उपज थी जो कि इसके द्वारा हरिजनों के साथ न्याय किया जा रहा है।

हरिजनों की समस्या पर कांग्रेस ने हमेशा जोर दिया है। बहुत से दोस्तों ने कहा है कि हरिजनों को बहुत ज्यादा दिया गया है। यह उनका अपना खयाल हो सकता है मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि उनके अन्दर आपसी मतभेद है। मैं बिहार के बारे में निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उनके बीच आपस में कोई मतभेद नहीं है। यू०पी० के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि वहां क्या हालात हैं। जब यू०पी० के इलैक्शन में मैं वहां गया था तो मैंने वहां यह इस किस्म की चीज नहीं

देखी। काफी सुधार हो चुका था पंडित जवाहर लाल नेहरू और महात्मा गांधी जी की बातों से और कार्यों से। जो कुछ यहां पर कहा गया वह बहुत पुराने जमाने या वैदिक काल में यह होगा। ये दकियानूसी बातें हैं मैं इन पर नहीं जाना चाहता हूँ।

अभी एक मैडम ने कहा जब वे भाषण दे रही थीं कि हरिजनों के साथ वेद मंत्रों या गायत्री मंत्र—

ओं भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नो प्रचोदयात् का उच्चारण नहीं कर सकते।

यह बिल्कुल गलत बात थी। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आज से बहुत दिन पहले, जब यहां हिन्दू संस्कृति में बहुत मतभेद हो गया था तो स्वामी जी ने जनता के बीच जागरण पैदा किया जिससे कि सब लोग उसे पढ़ सकते थे।

“औरतों की कोई जाति नहीं होती है। यदि वे वेद मंत्र सुन ले तो कान में सीसा पिघलाया जाता था, हरिजनों को नहीं पिघलाया जाता था।” मैं सुन रहा था उस वक्त बड़े गौर से उनका भाषण। किसी को भी इतना जजबाती नहीं रहना चाहिए जिससे कि मुल्क के दूसरे सेक्टर के लोगों को तकलीफ न पहुंचे। 20-सूत्री कार्यक्रम को अपनाते वक्त इसको रखा गया। पहले यह लागू नहीं होता था। बड़े बड़े बलिष्ठ नेता लोग थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, हमारे रेस्पेक्टेड गोविन्द वल्लभ पंत भी थे रफी साहब भी थे और मौलाना आजाद भी थे। लेकिन यह लागू नहीं होता। अब बड़ी हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ हमारी मोहतरमा प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बीस-सूत्री कार्यक्रम रखा है जिसके जरिए हिन्दुस्तान के अन्दर न कोई गरीब होगा न कोई अमीर होगा, समाज को एक लेबल में आना होगा। मैं कोई बहुत ज्यादा चर्चा में जाना नहीं चाहता हूँ लेकिन इस मुल्क की तवारीख है.....

उप-सभाध्यक्ष (श्री रणवीर सिंह) : चौधरी साहब, आपने 2 मिनट चाहा था, अब 5 मिनट हो गए हैं।

डा० चन्द्रमणि लाल चौधरी : मैं खत्म करता हूँ। तो मुल्क की तवारीख है जहां गांधी जी जैसी

[डा० चन्द्रमणि लाल चौधरी]

हस्ती पैदा हुई, हड्डियों का दान करने को उन्होंने कहा। हम मानते हैं हिन्दुस्तान एक गरीब मुल्क है, उसमें लोग गरीबी में जकड़े हुए हैं, कोई तो पड़े लिखे न होने की वजह से और कोई समाज के अन्दर शोषण की वजह से। आपको पता है हिन्दुस्तान के अन्दर दकियानुसी वक्त में सती की प्रथा थी, औरतों को गौहर मरने के बाद जिंदा जला दिया जाता था। इस प्रथा को रोका गया और हमारे बड़े बुजुर्गों ने रोका। पहले औरतें बाहर नहीं निकलती थीं। ये जो औरतें यहां बैठी हैं उनके ऊपर बुर्का होता, ये पार्लियामेंट में नहीं आ पाती लेकिन यह जवाहरलाल नेहरू की तारीफ थी (*Interruptions*) अब तो महिलाएं खुल कर बाहर आ रही हैं और यह युग महिलाओं का है। आज हरिजन भी उतने दबे हुए नहीं हैं जितना पहले दबे हुए थे। आज हरिजनों के ऊपर ज्यादाती होती है तो वे उसका मुकाबला करते हैं। यह बड़ी ताकतवर लीडरशिप है हमारी मोहतरमा इंदिरा गांधी की। जिनको यकीन नहीं है वे शरा 20-सूत्री कार्यक्रम को देखें। मैं उम्मीद करता हूं, हमारे दोस्तों ने जो गवर्नमेंट पर चाज लगाया है वह मा-हमल नहीं होगा। जय हिन्द।

SHRI OM MEHTA : Sir, I am very grateful to the honourable Members for the unanimous support that they have given to this Bill and I am grateful particularly to Shri Prakash Veer Shastri, Pandeji

—Unfortunately, I was not present here. But it was a very good speech, I must say— and then to Mr. Vaishampayan, Mr. Kumbhare—I think, Sir, Mr. Kumbhare has not spoken . . .

SHRI N. H. KUMBHARE : I had no opportunity to speak.

SHRI OM MEHTA : Sir, he has given an amendment and so, I thought that he must have spoken. I am grateful to Mr. Kalp Nath Rai, Rani Sahiban, Mr. Makhwana and many others. I am really thankful to all of them.

Sir, this is a very significant Bill. This was before the Lok Sabha for the last two years. Unfortunately, for one reason or the other, it could not be passed. It is good that it is being passed today and it is a very significant achievement so far as eradication of untouchability is concerned which, Sir, is a malady of our times. Sir, the word "untouchability" has been removed from our Constitution and this word is not there now. But untouchability is still practised in some parts of the country and it is a matter of shame for this country and for the people of this country who still practise it and I think it is high time that we took stringent action against those who still practised untouchability and to meet this need, Sir, we have brought forward this Bill.

Even before this Act came into being, we were not oblivious of this fact. Our beloved Prime Minister wrote to the Chief Ministers of all the States to set up special cells under their personal supervision to look into the grievances of the Scheduled Castes and Scheduled Tribe people and other minorities. Such cells have been set up in a number of States. Not only this, Sir. The Home Ministry has been issuing instructions from time to time to the States to look into the grievances of these downtrodden people, these exploited people, and we have issued instructions to them to the effect that in each and every State, the district officers must be requested to obtain relevant information about all incidents involving the Harijans, irrespective of whether such incidents have arisen due to any caste consideration or not and send it to the State and Central Governments since communication of such information to the State and the Central Governments would help them in placing these matters in proper perspective.

Sir, we have said that investigation of all offences involving Harijans, where any caste considerations are suspected, should be promptly, efficiently and adequately supervised. Investigation of serious offences involving the Harijans, where caste considerations are suspected, should be treated as special report cases and entrusted to selected

investigation officers. A suggestion made that such investigation should be conducted by an officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police or Inspector of Police, was adopted wherever possible. Any failure to undertake prompt and efficient investigation or to exercise adequate supervision should be regarded as grave dereliction of duty on the part of the officers concerned.

Sir, it can now be confidently said that a new orientation has been imported into the official approach—A steady improvement has also been made in regard to the administrative response to the needs of the situation.

Sir, my friend, Mr. Vaishampayan has quoted some figures also to show that in Gujarat and Maharashtra the number of atrocities is increasing. He gave figures for 1972, 1973, 1974, 1975. Sir, there is no doubt that previously whenever atrocities were committed they were not being reported. The Harijans were thinking that there would be retaliation from the higher castes and they were reluctant to report these atrocities to the *thana* or to the Government. Now, as the consciousness is growing, education is growing more and more such incidents are being reported. Sir, as politically, also they are becoming more and more conscious of their rights and privileges they are bringing more and more such incidents to the notice of the authorities.

Some points have been raised here that against these officers who are negligent or who do not register the cases whenever these poor people go to the police station, action should be taken. The present Bill is only to meet that situation. Where we find that there is a wilful negligence on the part of any officer to take any action against those who commit atrocities or to write the reports, action would be taken against that officer also.

Sir, not only that. We have said that in the case of those officers who do not go to the rescue of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the offence will be a cognizable offence and there also action will be taken against him.

Shri Makwana raised a point about the services. Sir, as I said in the other House, in this Bill we could not bring a provision for the services. But the Government is trying that whatever quota is fixed, it should be filled completely. Sir, I have been saying repeatedly in this House that full quota of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been filled in the all-India services, that is, I.A.S., I.P.S., T.F.S., in the past.

Wherever their representation is less, not only in Class IV services, but in Class I, Class II and Class III services also, in recent years we have tried to see to it that their number is increased. I should say that the number of Scheduled Castes officers is 35,061 in Class I, 54,129 in Class II, 16,32,397 in Class III and 12,38,818 in Class IV. In recent years, we have taken certain more steps. Reservation in promotion quota now applies to all the grades and classes where the element of direct recruitment does not exist, it is 66.33 per cent. Earlier this limit was 50 per cent. From 1974, recruitment to posts filled by selection has been extended to promotions from Class III to Class II, within Class II and from Class II to the lowest rung of Class I. Before 1974, such reservations were confined to Class III and Class IV posts. Carryforward provisions have been liberalised in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes with effect from June 1975. Scientific and technical posts for research up to the lowest grade of Class I have been brought within the purview of reservation orders. Earlier, no reservation existed for such posts. The U.P.S.C. and other competent authorities have been authorised to lessen qualifications relating to experience if otherwise suitably qualified Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates are available. The position has also improved in the public sector undertakings where the representation of Scheduled Castes has risen by 26.5 per cent in Class IV and 14 per cent in Class III. In the case of Scheduled Tribes, the representation has risen to 12 per cent and 6 per cent respectively.

Sir, a High-Power Committee under the chairmanship of the Prime Minister meets regularly to review the progress relating to

[Shri Om Mehta] matters concerning Scheduled Castes and Scheduled Tribes including their representation in services. Instructions have also been issued that reservation orders will apply to staff recruited by voluntary agencies which receive substantial grants-in-aid from the Government under certain conditions. We have seen to it that whatever orders are being issued by the Government of India, Department of Personnel, are implemented. It is not only the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes who keeps an eye on this. Also, a High-Power Committee of both the Houses of Parliament, which is there, looks to it whether the orders issued by us are implemented or not. The report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and also the report of the High-Power Committee of both the Houses of Parliament are placed on the Table of the House.

A point has been raised here by Mr. Wajid. He said that lakhs and lakhs of Harijans and other backward class people are still houseless.

SHRI SIKANDER ALI WAJID : I said about nomads.

SHRI OM MEHTA : Nomads are those who have got no lands and no houses. When I talk of houseless people, that means nomads also. It does not mean that we are excluding them. We are proud of what we have done during the last two or three years under the leadership of our hon. Prime Minister. There are lakhs and lakhs of houseless people. *(Interruptions)*. No, I am not yielding. He has said whatever he wanted to say. Sir, apart from whatever Mr. Wajid has said, I have high regards for his ability, for his experience, for his poetry and also other things.

I think, Sir, he has seen the figures of what has been achieved after the launching of the 20 point programme. The first priority which we are giving in this is to giving houses to the houseless. That is agricultural labour and those who are without houses. Sir, up to this time, 70 lakh people have been provided with house sites. Not only that. We are seeing to it that actually their possession is given to those people

who never had any house-sites up to this time and they should be able to build the houses there. When we talk of houses, I must say, in Delhi, when I was in the Housing Ministry, it was for the first time that we made a reservation of 20 per cent for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in all the flats which were being built by the DDA. We started separate reservations for the Harijans. Previously, a common list was being kept and, unfortunately, from the Janata houses and other houses, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes were not getting any houses. So, we made it a special thing that 20 per cent of the houses built by the DDA would be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and they would get priority in that. Not only that, Sir, the money which was to be paid by them as first instalment or as registration fee was also reduced considerably. And there is no discrimination. For persons who are without houses, whatever possible is being done to give them houses so that they can also live a happy and contented life.

Sir, some other points have been made by the hon. Members. Shastriji made a point that there are separate schools for the Harijans. Sir, I should inform Shastriji that there are no separate schools. We allow other boys also to come to the Ashram school and schools which are opened for Harijans. But generally what happens is this. Mostly the schools which are opened for Harijans are in areas where their population is predominant. And as Mr. Makwana says in many of the schools, they have got 10 per cent reservation but many students do not come there. When we talk of untouchability, we do not want that. But still we should take certain steps by which this untouchability is not perpetuated. In schools and other places, we want that Harijan boys should be allowed to sit with other boys so that from the very beginning this idea that they are untouchables is not there in their minds.

SHRI ABU ABRAHAM : What about the reservation of 20 per cent? You were saying that 20 per cent of the housing is reserved for Harijans. Could you please tell

us whether these houses will be separated for Harijans or will they be mixed houses ?

SHRI OM MEHTA : They will be mixed houses. This is only reservation. But it is not that we will fix certain blocks only for Harijans where the Harijans live. They will live with other communities in any colonies and wherever the houses are there.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAN-BIR SINGH) : The question is :

"That the Bill to amend the Untouchability (Offences) Act, 1955 and further to amend the Representation of the People Act, 1951, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAN-BIR SINGH) : We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 16 were added to the Bill.

Clause 17—Substitution of section 15.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAN-BIR SINGH) : There is one amendment by Shri Kumbhare.

SHRI N. H. KUMBHARE : Sir, I did not have any opportunity to speak on the Bill. I am in entire agreement with the hon. Minister when he says that it is a really radical measure. The Bill is, no doubt, comprehensive and it is also more purpose-full: I say the scope of the Bill is also enlarged.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : Are you moving the amendment?

SHRI N. H. KUMBHARE : I am just coming to the amendment. I am just making the opening remarks.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : May I know whether you are moving the amendment?

Would you like to speak on the clause ?

SHRI N. H. KUMBHARE : Sir, I move :

"That at page 8, after line 7, the following be inserted namely :

"A survey of the district will be conducted by Assistant Director of Civil Rights for locating the area of social disability in such manner as prescribed and shall submit a report a.s to the nature of untouchability being practiced and the extent of social disability to which the Scheduled Caste people are subjected.

Explanations : 'Area of social disability is a place or places where members of Scheduled Castes, on account of their subjection could not exercise their right, accrued to them, by reason of the abolition of untouchability under Article 17 of the Constitution.

(1) On receipt of the report from the Assistant Director and after making an enquiry as may deem appropriate and on being satisfied as to the situation existing at the place, the Director of Civil Rights will make a declaration specifying the area of social disability and other particulars as may be prescribed.

(2) The area of social disability having been so declared the Assistant Director shall proceed to take such steps and in such manner as may be prescribed to deal with the situation, and shall endeavour to persuade the dominant class through conciliation and seek to create condition so that the members of the Scheduled Castes do not suffer from any social disability provided the said area will be kept under observation for such period as may deem necessary. Provided further the period of observation will not be for a period exceeding six months.

(3) The Assistant Director of Civil Rights after having succeeded in his efforts in creating favourable conditions submit a report to the Director who will make a declaration accordingly, in the manner as may be prescribed.

[Shri N. H. Kumbhare]

(4) The Assistant Director of Civil Rights having satisfied that he has failed in his efforts to create favourable conditions to facilitate enforcement of rights by members of the Scheduled Castes, submit a failure report to the Director of Civil Rights. This report shall contain the particulars as may be prescribed including the names of the persons who are likely to commit or attempt to commit or abets the commission of an offence.

(5) (A) The Sub-Divisional Magistrate having jurisdiction and specially empowered by the State Government in this behalf, will be given information of the persons referred to in the failure report by the Assistant Director of Civil Rights and the S.D.M. may require such persons to show cause why they should not be ordered to execute bond with surety for their good behaviour for such period not exceeding 3 years as the Magistrate may direct.

(B) The Provision of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall in so far as they are applicable apply to any proceedings under sub-section (1) as if the bond referred to therein were a bond required to be executed under section 110 of the said Code'." *The question was proposed.* SHRI N. H. KUMBHARE : Sir, formerly only practice of untouchability was forbidden but now not only practice but preaching of untouchability is also forbidden. If anybody preaches or practises now he will be dealt with and will come under the clutches of the Law. Therefore, I say that the scope of the Bill has been enlarged. It has been made more deterrent because these offences have now been made cognizable. It is also non-bailable. If anybody is found guilty the magistrate has no discretion except to send him to jail because the minimum jail sentence is one month.

Sir, I would be failing in my duty if I do not say a word about the good work of the Joint Select Committee which was presi-

ded over by Mr. S. M. Siddiah. Mr. Mirdha was the Minister in charge of the Bill. But for their-cooperation it would not have been possible to give such a good shape to it. I may however point out that it could have been made more comprehensive we could have incorporated a scheme by which we could locate the areas of untouchability and deal with those areas. It is essentially a matter which comes within the purview of the Central Government and we desire that the Central Government should set up a machinery to enforce these provisions. As has been pointed out by my friends, laws are there. But laws become dead letters if we do not set up an administrative machinery to enforce those laws and therefore we want them to take the entire responsibility in this behalf and Government should set up a machinery to enforce these provisions. Unfortunately that suggestion has not been accepted and the entire responsibility has been transferred to the State Governments. Of course, under the Act itself the Central Government will make the rules whereby a duty will be cast on the State Governments to set up a machinery. I have stated that Government must make the entire provisions more explicit and, therefore, in regard to my amendment, I only want to cite an example. Even today if you go to a village there will be a well. If that well is located in a high caste locality, the Scheduled Caste people will not be allowed to fetch water from that well. So, according to me, it is an area of disability.- Such areas have to be identified and located. Let the Government play a more positive role. I have suggested that an officer should be appointed under the Act. A duty will be cast on the officer to have a survey made to find out how many places are there where the Scheduled Caste people, even though they have got a right given under the Constitution, are denied those rights. The reasons are obvious. They know that they have got a right but they cannot muster courage to assert that right because they are in a minority, because they have to depend upon them. In such a case the officer will go and find out himself how the position is. He will make an enquiry and if he comes to the conclusion

that even though on the face of it there appears to be no discrimination, the caste Hindus are dominating and practising untouchability and preventing these people from taking water, suitable action should be taken.

So, in that case, under the survey, that area will be identified as an area of social disability. The Government will notify it and then there will be a stage of conciliation. As I said, the officer will go and try to bring about a conciliation and tell those elements that these are the provisions in the Act and that they must allow the scheduled castes otherwise they will have to suffer and go to jail. In that way, I think, people in the village will not be opposed to it. But, if there are certain elements still, the officer will make a note of those bad elements who are opposed to it and then he will make a report to the Director and the Director will file proceedings in the court. The court will then issue summons to them and tell them that they must create conditions whereby the Scheduled Caste people would have full freedom to go and fetch water. That is the scheme which is incorporated and I think it should be acceptable to Government.

Unfortunately, Sir, one of the important recommendations has not been accepted by the Government. It reads like this .

"A public servant who shows any negligence in the investigation of any offence punishable under the Act shall be deemed to have abetted the offence punishable under this Act."

I know the reasons and that way I am convinced that if the Government is going in for a separate legislation providing for reservations for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, then such a provision could find a place. So, we would like to know from the hon. Minister whether such a legislation is under contemplation. And if so, when are we going to have it ?

SHRI OM MEHTA : Sir, I have already replied to points raised by the hon. Member. Whatever he has said with regard to recruitments and other things, I have already I

given an assurance that we are trying to see whether orders issued by our Ministry are being implemented or not. Still, if he finds that they are not being implemented, we will have to codify these orders and find out how a suitable legislation can be brought in. We can consider it only after taking stock of the whole thing.

Sir, I must tell Mr. Kumbhare that by article 17 of the Constitution, untouchability has been abolished and disability arising out of untouchability has been declared to be an offence. Under article 35(a), sub-section (ii), Parliament has the exclusive legislative competence to provide for punishment for enforcement of the disability arising out of untouchability. The Act in question, fe, therefore, restricted to the above-mentioned constitutional provision.

Sir, in this particular Bill, we also have got some provision for the machinery for the enforcement of this Act. Under that provision, some officers will certainly be appointed who will be going to find out if there are certain places where the Harijans who are very poor or in minority, are not able to take the shelter of the law or are not able to go to those whom they can go for protection. These officers will report about those areas and, as you know, Sir, we have got a provision of collective fines from those villages and that action will be enforced. That provision has also been kept.

Sir, with these words, I oppose this amendment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAN-8IR SINGH): Mr. Kumbhare. do you want to withdraw the amendment ?

SHRI N. H. KUMBHARE: Yes. Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAN-BIR SINGH) : The question is :

"That leave be granted to the Movci to withdraw the amendment."

The motion was adopted.

The amendment was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN 'SHRI RAN-BIR SINGH): The question is:

"That clause 17 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clauses 18 to 21 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill. SHRI

OM MEHTA : Sir. I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

STATEMENT BY MINISTER REGARDING BAN ON COW SLAUGHTER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): Sir, this morning, I promised that I will make a statement regarding the ban on cow slaughter. Though the subject is dealt with by the Agriculture Ministry, since it is the last day of the Session and since the concerned Minister is not here, I am making the statement on behalf of the Government.

Questions have been raised from time to time in Parliament regarding steps taken by various State Governments in regard to the implementation of the provision contained in article 48 of the Constitution relating, *inter alia* to **ban** on cow slaughter.

The Supreme Court has interpreted the effect of article 48 of the Constitution relating to prohibition of slaughter of cows and its progeny, as follows :—

(a) That a total ban on the slaughter of cows of all ages and calves of cows and calves of she-buffaloes, male and female, is quite reasonable and is in consonance with the Directive Principles as laid down in article 48 ;

(b) That a total ban on the slaughter of she-buffaloes, or breeding bulls or working bullocks, as long as they are capable of being used as milch or draught cattle, is also reasonable and valid; and

(c) That a total ban on the slaughter of she-buffaloes, bulls and bullocks, after they cease to be capable of yielding milk or of breeding or working as draught animals cannot be supported as reasonable in the interest of the general public and is invalid.

The subject of preservation, protection and improvement of stock comes under Entry 15 of List II of the Seventh Schedule to the Constitution and as such 'his is a State subject. Although the responsibility is of the States, the Centre has been advising them in the matter.

The present position in respect of restrictions on cow slaughter varies from State to State, Jammu & Kashmir, Haryana, Punjab, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra (Vidarbha Region), Karnataka, Orissa, Chandigarh, Delhi, Dadra & Nagar Haveli, Pondicherry and Andaman & Nicobar Islands have completely prohibited cow slaughter. In Himachal Pradesh, Tripura and Manipur valley, there is a total ban either by tradition or under executive orders. There are only a few States and Union Territories, where there is either partial ban or no ban.

Information has now been received that States of Maharashtra, Andhra Pradesh, Assam excluding hill districts of North Cachar and Mikir) and Tamil Nadu have decided to take appropriate measures to provide for ban on the slaughter of cows in terms of the Supreme Court's judgment. The States of Andhra Pradesh, Maharashtra and Assam would be amending the existing legislation whereas State of Tamil Nadu which is presently under President's Rule have issued an executive order prohibiting the slaughter of cows of all ages and calves (male and female) of cows. In Kerala, there is no legislation prohibiting the slaughter of animals. Only panchayat laws provide for prohibition of the slaughter of useful ani-